



लुंगीवाला विवाद, विशेषाधिकार हनन का नोटिस

नई दिल्ली। राज्यसभा में सीपीआई (एम) सांसद जॉन ब्रिटাস और भारतीय जनता पार्टी की सांसद सुष्मिता देव के बीच विवाद काफी बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बुधवार को बीजेपी सांसद के खिलाफ सीपीआई (एम) नेता ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया।

यह घटना सीपीआई (एम) सांसद जॉन ब्रिटাস के उस आरोप के कुछ घंटों बाद हुई, जिसमें उन्होंने कहा था, सत्ता पक्ष के एक सदस्य ने सोमवार को उनके भाषण के दौरान उनके पहनावे पर

अपमानजनक टिप्पणी की और उन्हें लुंगीवाला कहा। जॉन ब्रिटাস ने कहा, मुझे भारतीय, दक्षिण भारतीय और मलयाली होने पर गर्व है। मुझे मलयाली होने के हर पल से प्यार है। हमारी भाषा, संस्कृति, खान-पान और निश्चित रूप से हमारा पहनावा।

जॉन ब्रिटাস ने सुष्मिता देव का नाम लिए सदन के एक सदस्य पर उन्हें परेशान करने और उनके पहनावे पर टिप्पणी करने का आरोप लगाया। ब्रिटাস ने कहा, कुछ दिन पहले, सदन के एक



सम्मानित सदस्य, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, उन्होंने मुझे तब परेशान किया जब मैं एक वैधानिक प्रस्ताव पेश करने की अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। बहस-

मुबाहिसा ठीक है। हम एक-दूसरे से लड़ते भी हैं। लेकिन उन्होंने बार-बार मुझे लुंगीवाला, लुंगीवाला कहा। मैंने धोती पहनी हुई थी सुष्मिता देव ने जवाब देते

हुए कहा, %न तो उन्होंने और न ही किसी अन्य सदस्य ने किसी राज्य के पहनावे पर कोई अपमानजनक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से ब्रिटাস से बात करने को तैयार हैं। जेपी नड्डा ने प्रस्ताव रखा कि गलतफहमी दूर करने के लिए दोनों सदस्य उनके चैंबर में आ सकते हैं। चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने कहा, %सदस्यों, मेरे ध्यान में कुछ ऐसी घटनाएं आई हैं जिनमें सदस्यों ने सदन में दूसरों के भाषण के दौरान असभ्य और अशोभनीय टिप्पणियां की हैं।

मेरी सलाह है कि माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखें कि वे साथी सदस्यों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। सीपी राधाकृष्णन ने कहा, हमारी संस्कृति अनोखी है और इसमें विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृतियां शामिल हैं। हमारे सहयोगियों की सांस्कृतिक परंपराओं और क्षेत्रीय पहचान का अनादर नहीं होना चाहिए। राधाकृष्णन ने आगे कहा, %अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है, तो मैं सभी सदस्यों को अपने चैंबर में आने के लिए आमंत्रित करता हूं।

विदेशी फंडिंग पर नजर रखने के लिए एफसीआरए जरूरी: रिजिजू

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू ने आज बुधवार, 12 अगस्त को सदन में बोलेते हुए विदेशी फंडिंग रेगुलेटरी बिल खिलाफ विपक्ष के गुमराह करने वाले अभियान की कड़ी आलोचना की। किरन रिजिजू ने कहा, भारत कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है और विदेशी फंड खर्च करने के लिए नियम-कानून होने चाहिए।

एफसीआरए को मिलने वाली विदेशी फंडिंग के रेगुलेशन में कमियों को दूर करने और धर्म-परिवर्तन को रोकने के मकसद से लागू एफ इस प्रस्तावित कानून की विपक्ष आलोचना कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि यह अल्पसंख्यक-विरोधी विधेयक है। विदेशी पूंजी के प्रवाह पर नजर रखने वाले इस एफसीआरए बिल को लोकसभा ने जेपीसी के पास भेज दिया। विपक्ष ने सवाल उठाया, एफसीआरए को आसानी से विदेशी चंदा कैसे मिल रहा है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने लोकसभा में कहा, एफसीआरए संशोधन बिल का कोई भी प्रविधान अल्पसंख्यक संस्थानों को निशाना नहीं बनाता है। विपक्ष कुछ समुदायों को गुमराह करने के लिए अभियान चला रहा है।



रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ का पहला पर्व हरेली तिहार आज बुधवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान प्रदेश के मुखिया सीएम विष्णु देव साय पारंपरिक वेशभूषा धारण कर पिंग ऑटो में सवार होकर सीएम हाउस पहुंचे। प्रदेशवासियों को हरेली तिहार की बधाई और शुभकामनाएं दी। कृषि आधारित छत्तीसगढ़ का पहला हरेली तिहार पूरे प्रदेश भर में पारंपरिक रीति रिवाज के साथ मनाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हरेली तिहार छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक परंपरा, संस्कृति और कृषि जीवन से जुड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। उन्होंने किसानों की खुशहाली की कामना करते हुए कहा कि इस बार प्रदेश में अच्छी बारिश हो। खेती-किसानी का काम बेहतर तरीके से संपन्न हो, ताकि किसानों के जीवन में समृद्धि आए।

1 लाख करोड़ की रक्षा खरीद को मिली हरी झंडी

नईदिल्ली। देश की सैन्य क्षमता को नई मजबूती देने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई डिफेंस एंक्रिजिशन कार्डसिल की बैठक में लगभग 1 लाख करोड़ के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस फैसले का मकसद तीनों सेनाओं को आधुनिक हथियारों और अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों से लैस करना है, ताकि भविष्य की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके।

ये बैठक कई मायनों में खास रही क्योंकि नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल राजा सुब्रमण्यम, सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ और नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन की मौजूदगी में ये पहली डीएसी बैठक थी. इसमें देश की सुरक्षा खतरों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण रक्षा परियोजनाओं पर सहमति बनी. बैठक में भारतीय सेना के लिए स्वदेशी Man Portable Anti-Tank Guided Missile (MP-ATGM) सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। इस परियोजना के तहत 100 लॉन्चर, 2,300 मिसाइलें और 5 आधुनिक सिमुलेटर खरीदे जाएंगे. इसकी अनुमानित लागत ₹2,600 करोड़ से अधिक बताई गई है. इस सिस्टम का निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड करेगा. ये मिसाइल दुश्मन के टैंकों और बखतरबंद वाहनों को सटीक निशाना बनाने में सक्षम होगी और सीमा पर तैनात सैनिकों की मारक क्षमता बढ़ाएगी। डीएसी ने भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए 600 एचएमएमईआर प्रिंसिजन एयर-टू-ग्राउंड मिसाइलों की खरीद को भी मंजूरी दी है।

जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग

■ शीतकालीन सत्र में बढ़ सकती है प्रक्रिया; जांच समिति ने लगाए यह आरोप



नई दिल्ली। केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिस्वा द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच समिति ने जस्टिस वर्मा को उनके सरकारी आवास से भारी मात्रा में बिना हिसाब-किताब वाली नकदी मिलने के मामले में दोषी पाया है। समिति ने बुधवार को संसद के दोनों सदनों में सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा कि जस्टिस वर्मा पर बिना हिसाब-किताब वाली नकदी रखने, सबूतों से छेड़छाड़ करने और टालमटोल वाला जवाब देने के आरोप साबित हुए हैं।

जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच के लिए यह समिति उस

समय गठित की गई थी, जब करीब 200 सांसदों ने संसद में उन्हें पद से हटाने की मांग की थी। लोकसभा अध्यक्ष ने जजेज (इन्क्रायरी) एक्ट, 1968 की धारा 3(2) के तहत तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था। जस्टिस वर्मा ने इसके बाद इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कानून मंत्रालय ने अभी तक उनके इस्तीफे की अधिसूचना जारी नहीं की है। उनका नाम अब भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की सूची में शामिल है।

घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले सूत्रों के मुताबिक, सरकार शीतकालीन सत्र में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सूत्रों ने कहा

कि आमतौर पर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के इस्तीफा देने पर उसे स्वीकार मान लिया जाता है। हालांकि, जस्टिस वर्मा के मामले में संसद में उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद इस्तीफा दिया गया था। इसी वजह से उनका इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। सूत्रों के अनुसार, सरकार एक मिसाल कायम करने और यह संदेश देने पर भी विचार कर सकती है कि गंभीर अनियमितताओं में शामिल होने के बाद कोई जज इस्तीफा देकर हटाने की प्रक्रिया से बच नहीं सकता।सरकारी आवास में करोड़ों की जली हुई नकदी मिलने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन जज जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे आरोप लोकसभा की जांच समिति ने सही पाए हैं। समिति ने कहा कि जस्टिस वर्मा पर नकदी का हिसाब न दे पाने सबूतों से छेड़छाड़ और टालमटोल वाला स्पष्टीकरण (आरोप 3) साबित होते हैं।

प्रमुख समाचार

मोदी ने युवाओं से कहा- रामनाथ कोविंद की आत्मकथा पढ़ें

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने युवाओं से आत्मकथाएं पढ़ने और दूसरों के संघर्षों से सीखने की बुधवार को अपील करते हुए कहा कि ‘रील के युग’ में रह रहे युवाओं को याद रखना चाहिए कि “शॉर्टकट आपको नुकसान पहुंचा सकता है।” मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति



रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ‘ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक: माय लाइफ, माय स्ट्रगल्स’ के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कोविंद का जीवन दिखाता है कि दृढ़ संकल्प किसी व्यक्ति को मुश्किलों से उबरने और सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने में कैसे मदद कर सकता है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी कोविंद के लगातार सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहने का जिक्र करते हुए कहा कि पद छोड़ने के बाद भी उन्होंने आराम नहीं किया, बल्कि ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पहल पर काम कर रहे हैं, जो “भारतीय लोकतंत्र में एक नया अध्याय खोल सकती है।” प्रधानमंत्री ने युवाओं से आत्मकथाएं पढ़ने की अपील की।

खरगे ने शाह से छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर मांगा जवाब

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग की। उन्होंने कहा कि विपक्ष संसद में अपना रुख बनाए रखेगा। पत्रकारों से बात करते हुए खरगे ने कहा, ‘कल कुछ नहीं होगा।



हम वही करते रहेंगे जो अब तक करते आ रहे हैं।’ बुधवार को विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और अमित शाह जवाब दो के नारे लगाए। विपक्ष ने राष्ट्रीय राजधानी और अन्य राज्यों में छात्रों के खिलाफ पुलिस की ओर से बल प्रयोग किए जाने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री पर निशाना साधा। इससे पहले दिन में, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्ड़ा ने शाह पर तीखा हमला किया। उन्होंने देश भर में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लाठी और पैलेट गन समेत बल के कथित इस्तेमाल के लिए सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता ने कहा, आपको क्या लगता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जब हजारों छात्र इकट्ठा होते हैं।

लुंगीवाला टिप्पणी पर भड़के सीपीआई(एम) जॉन ब्रिटাস

नईदिल्ली। सूत्रों के मुताबिक, सीपीआई(एम) के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटस ने भाजपा सांसद सुष्मिता देव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सदन की कार्यवाही के दौरान



देव ने बार-बार उनके लिए लुंगीवाला शब्द का इस्तेमाल किया, जो सांस्कृतिक और क्षेत्रीय अपमान के बराबर है। ब्रिटस ने राज्यसभा में कामकाज के संचालन और प्रक्रिया के नियम 188 के तहत यह नोटिस दिया। उन्होंने देव की टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला उठाने की अनुमति मांगी। जॉन ब्रिटस ने कहा, भारी मन से मैं यह मुद्दा उठा रहा हूं, क्योंकि यह इस सदन की गरिमा, प्रतिष्ठा और सम्मान का सवाल है। यह किसी एक दल का नहीं, बल्कि सभी दलों से जुड़ा मुद्दा है। ब्रिटस का आरोप है कि देव ने ये टिप्पणियां तब कीं, जब वह सोमवार को टैक्स लेने के लिए कामकाज पर चर्चा के दौरान सदन में बोल रहे थे।

नसीरुद्दीन शाह खाते देश का हैं लड़ते पड़ोसी के लिए है : कंगना

नईदिल्ली। दिल्ली में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान बॉलीवुड सेलेब्रिटीज की चुप्पी पर नसीरुद्दीन शाह की टिप्पणी से शुरू हुई बयानबाजी के बीच, एक्टर और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने अनुभवी एक्टर पीयूष मिश्रा द्वारा नसीरुद्दीन शाह की



आलोचना का समर्थन किया है। रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर मिश्रा के हालिया बयानों वाली एक समाचार रिपोर्ट साझा की और सीधे नसीरुद्दीन शाह को संबोधित किया। शाह द्वारा कुछ मशहूर हस्तियों की तुलना मुंह में हड्डी वाला कुत्ता जो भौंक नहीं सकता से की गई तुलना का जिक्र करते हुए, रनौत ने लिखा कि सच तो ये है हर कोई किसी ना किसी का कुत्ता है, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि मैं जिस घर (देश) की रोटी खाती हूं उसकी रखवाली करती हूं/उसके लिए लड़ती हूं। नासिर साहब खाते तो इस देश का हैं लेकिन लड़ते पड़ोसी देश के लिए हैं। उन्होंने आगे कूते से तुलना का बचाव करते हुए कहा कि आज के समय में इंसानों को कुत्ता कहलाना एक तारीफ है क्योंकि वफादारी और क्यूटनेस बहुत दुर्लभ है।

तमिलनाडु विधानसभा में परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव पारित

चेन्नई। तमिलनाडु विधानसभा ने बुधवार को प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में मांग की गई है कि लोकसभा सीटों की संख्या 543 ही बनी रहे और इसी संख्या के आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया जाए। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री विजय ने



विधानसभा में कहा, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण मौजूदा 543 निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर 2029 के लोकसभा चुनावों में ही लागू किया जाना चाहिए। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण में और देरी नहीं होनी चाहिए। तमिलनाडु में पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाओं ने मतदान किया है। महिलाओं को आरक्षण देना कोई रियायत नहीं है; यह सामाजिक न्याय का मामला है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिना किसी और देरी के लागू किया जाना चाहिए। प्रस्ताव में तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या को स्थायी रूप से 543 पर बनाए रखा जाए, जैसा कि अभी है। प्रतिनिधित्व के मौजूदा अनुपात के आधार पर लोकसभा सीटों के अंतर-राज्यीय आवंटन को स्थायी रूप से बनाए रखा जाए।

अधर में फलस्तीन का भविष्य

ट्रंप के दावों के बावजूद शांति योजना पर संशय बरकरार

मार्टिन कीर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हमास और गाजा के अन्य चरमपंथी संगठन हथियार छोड़ने पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने इसे गाजा में स्थायी शांति और सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। ट्रंप के अनुसार, हमास के निरस्त्रीकरण से फलस्तीनी समिति गाजा का प्रशासन संभाल सकेगी और इस्राइली सेना को वहां से हटने का रास्ता मिलेगा। यह कदम उनकी 20-सूत्री शांति योजना का हिस्सा है, जिस पर पिछले साल अक्टूबर में हमास और इस्राइल ने सहमति जताई थी।

हालांकि, हमास के अधिकारियों ने कहा है कि वे इस प्रक्रिया पर सहमत हैं, लेकिन बातचीत में शामिल एक सदस्य ने चेतावनी दी कि उनका हथियार

छोड़ना तभी संभव होगा, जब इस्राइल गाजा से पूरी तरह अपनी सेना वापस बुला ले। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या यह वास्तव में शांति की दिशा में निर्णायक कदम है, या अब भी बहुत सारे सवाल अनसुलझे हैं?

यदि हमास वास्तव में पूरी तरह हथियार छोड़ने पर सहमत हो जाता है, तो यह वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूर्वी यरुशलम पर इस्राइली कब्जे के खिलाफ करीब चार दशक से चल रहे संघर्ष में उसकी ओर से एक बड़ी रियायत होगी। हमास की शुरुआत 1987 में दो लक्ष्यों के साथ हुई थी- इस्राइली कब्जे का विरोध करना और फलस्तीनी राजनीति में फतह पार्टी के वर्चस्व को चुनौती देना।

अपने 2017 के चार्टर में हमास ने स्पष्ट कहा था कि वह प्रतिरोध और उसके हथियारों को कमजोर करने की

किसी भी कोशिश को खारिज करता है। संगठन के अनुसार, सशस्त्र संघर्ष फलस्तीनी जनता के सिद्धांतों और अधिकारों की रक्षा के लिए एक रणनीतिक विकल्प है। इसके अलावा, फलस्तीनियों के बीच हमास की वैधता का मुख्य आधार उसका सशस्त्र प्रतिरोध ही है। फलस्तीनियों के लिए, यह प्रतिरोध एक स्वतंत्र देश का दर्जा हासिल करने की कोशिशों से जुड़ा हुआ है। यानी भले ही कई फलस्तीनी राजनीतिक रूप से हमास या उसके इस्लामी एजेंडे का समर्थन न करते हों, फिर भी वे इस आंदोलन का सम्मान करते हैं। उनके लिए इस्राइली कब्जे के खिलाफ हमास का लगातार सशस्त्र प्रतिरोध या तो फलस्तीनी राष्ट्र की मांग को मजबूत करता है या फिर इस्राइल के स्थायी कब्जे की कोशिशों को चुनौती देता है।



अक्टूबर 2025 में पीपल्स सेंटर फॉर पॉलिसी एंड सर्वे रिसर्च (पीसीपीएसआर) के सर्वे के अनुसार, 60 फीसदी फलस्तीनियों (वेस्ट बैंक में 66 प्रतिशत और गाजा में 51 फीसदी) ने हमास के प्रदर्शन पर संतोष जताया। वहीं, 69 प्रतिशत लोग (वेस्ट बैंक में 87 फीसदी और गाजा में 55 प्रतिशत) गाजा पट्टी में हमास के हथियार छोड़ने के खिलाफ थे। इसे देखते हुए, यह मानना मुश्किल है कि हमास

फलस्तीनियों के बीच अपने इस समर्थन को जोखिम में डालेगा। शुरुआती मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, हमास के निरस्त्रीकरण का मतलब केवल हथियार सौंपना नहीं होगा, बल्कि गाजा में उसके पूरे सैन्य ढांचे को खत्म करना भी होगा। इसमें सुरंगों का नेटवर्क, भारी हथियार, हथियार बनाने के केंद्र और गोला-बारूद के भंडार भी शामिल हैं। हालांकि, गाजा में हुई व्यापक तबाही ने देखते हुए यह साफ नहीं है कि इस सैन्य ढांचे का कितना हिस्सा अब भी बचा है। इसी तरह, हमास के पास फिलहाल कितने हथियार हैं, इसकी भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, उसके पास अब भी हजारों ऑटोमैटिक राइफलों और एंटी-टैंक रॉकेट जैसे भारी हथियार हो सकते हैं,

लेकिन उनकी वास्तविक संख्या पहले के मुकाबले काफी कम मानी जा रही है। कई अन्य अहम सवाल भी अभी अनुत्तरित हैं। मसलन, हमास से हथियार कौन लेगा और यह कैसे तय होगा कि उसने वास्तव में सभी हथियार सौंप दिए हैं? एक अमेरिकी अधिकारी ने बीबीसी से कहा कि उसके लिए किसी तीसरे पक्ष की समिति यह जिम्मेदारी निभाएगी, लेकिन इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं दी गई।

इसके अलावा, हमास सिर्फ गाजा पट्टी तक सीमित नहीं है। उसकी मौजूदगी वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम में भी है। ऐसे में, यह स्पष्ट नहीं है कि निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया संगठन के उन हिस्सों पर भी लागू होगी या नहीं। वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम में कट्टरपंथी यहूदियों की ओर से फलस्तीनियों पर लगातार हो रही हिंसा को देखते हुए,

इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि हमास या अन्य फलस्तीनी सशस्त्र आंदोलनों के सदस्य अपनी हिंसा के जरिये इस हिंसा का विरोध करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में, हथियार छोड़ने और गाजा का प्रशासन किसी अन्य व्यवस्था को सौंपने पर सहमत होना हमास की ओर से एक रणनीतिक कदम हो सकता है। इससे समूह को इस्राइल से मिली भारी शिकस्त के बाद संगठनात्मक रूप से उबरने में मदद मिल सकती है, साथ ही व्यापक फलस्तीनी आवादी के बीच अपने प्रतिरोध के एजेंडे को बनाए रखने में भी मदद मिल सकती है।

इस समझौते पर इस्राइल की प्रतिक्रिया सबसे बड़ी चुनौती है। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, इस्राइली सरकार ट्रंप की इस शांति योजना पर आपत्ति जता रही है।

देशभर में दिखेगी बस्तर की संस्कृति

सांसद महेश कश्यप ने केंद्रीय मंत्री से की मुलाकात, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का दिया प्रस्ताव

जगदलपुर। बस्तर की करीब 800 वर्ष पुरानी सांस्कृतिक विरासत को देश-दुनिया तक पहुंचाने की पहल तेज हो गई है। बस्तर सांसद महेश कश्यप ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर बस्तर दशहरा के दूरदर्शन और आकाशवाणी से विशेष प्रसारण की मांग रखी। शहरऔर स्थानीय मार्गदर्शिका सांसद महेश कश्यप ने बस्तर दशहरा की परंपरा, जनजातीय संस्कृति और बदलते बस्तर पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का भी प्रस्ताव दिया।

उनका कहना है कि बस्तर अब नक्सलवाद की पहचान से आगे बढ़कर शांति, विकास और समृद्ध संस्कृति की नई तस्वीर पेश कर रहा है। वहाँ जगदलपुर-



रावघाट रेल परियोजना में कार्य शुरू होने की दिशा में हुई प्रगति के लिए सांसद ने केंद्रीय मंत्री का आभार जताया।

सांसद कश्यप के प्रस्ताव पर अश्विनी वैष्णव ने संबंधित

अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। दूरदर्शन आकाशवाणी और डॉक्यूमेंट्री के जरिए बस्तर की संस्कृति और बदलते स्वरूप को राष्ट्रीय मंच मिलने की उम्मीद है।

बस्तर दशहरा 2026: पाट जात्रा पूजा से 75 दिनी ऐतिहासिक पर्व की आज से होगी शुरुआत

बलौदाबाजार-भाटापारा। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की आज से शुरुआत होगी। 12 अगस्त को बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी की पाट जात्रा पूजा के साथ बस्तर दशहरा पर्व का आगाज होगा। इस दौरान पारंपरिक मांडी-चालकी, मेम्बर-मेम्बरीन, पुजारी, पटेल, नाइक-पाइक और सेवादार रथ निर्माण के लिए औजार बनाने की रस्म अदा करेंगे। बस्तर दशहरा समिति ने सभी सेवादारों, ग्रामीणों और गणमान्य नागरिकों को इस पूजा विधान में शामिल होने का अनुरोध किया है।

मां दंतेश्वरी को समर्पित 75 दिवसीय दशहरा पर्व अपनी अनूठी लोक-परंपराओं, जनजातीय संस्कृति और शानदार रस्मों के लिए विश्व विख्यात है। 75 दिनों तक चलने वाले बस्तर



दशहरा का मुख्य कार्यक्रम जारी किया गया है। 12 अगस्त बुधवार से पाट जात्रा पूजा विधान दशहरा पर्व का शुभारंभ होगा। 24 सितम्बर को डेरी गड़ाई पूजा विधान, 10 अक्टूबर शनिवार को काछनगादी पूजा विधान, 11 अक्टूबर रविवार को कलश स्थापना पूजा विधान, 12 अक्टूबर सोमवार को जोगी बिठाई पूजा विधान के रस्म का आयोजन किया जाएगा। 13 अक्टूबर से 18 अक्टूबर को प्रतिदिन नवरात्रि पूजा एवं रथ परिक्रमा पूजा विधान, 18 अक्टूबर रविवार को सुबह 11 बजे बेल पूजा विधान,

19 अक्टूबर सोमवार को महाअष्टमी पूजा विधान एवं निशा जात्रा पूजा विधान, 20 अक्टूबर मंगलवार को कुंवारी पूजा विधान, जोगी उठाई पूजा विधान एवं मावली परघाव होगा। 21 अक्टूबर बुधवार को भीतर रैनी पूजा विधान एवं रथ परिक्रमा, 22 अक्टूबर गुरुवार को बाहर रैनी पूजा विधान एवं रथ परिक्रमा, 23 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह काछन जात्रा पूजा विधान, दोपहर में ऐतिहासिक मुरिया दरबार लगेगी। 24 अक्टूबर शनिवार कुटुम्ब जात्रा पूजा विधान ग्राय्य देवी-देवताओं की विदाई, 27

नीट-यूजी की आएएमआर शीट में नहीं मिली गड़बड़ी

हाईकोर्ट ने छात्रा की याचिका की खारिज



बिलासपुर। हाईकोर्ट ने नीट की छात्रा की ओएमआर शीट में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल के बेंच ने मूल ओएमआर शीट की जांच के बाद यह निर्णय लिया। कोर्ट ने पाया कि छात्रा ने कुल 180 में से केवल 71 प्रश्नों के उत्तर दिए थे, जिनमें 46 सही और 25 गलत थे। कोर्ट ने कहा कि मूल ओएमआर शीट परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा दर्ज उत्तरों का वास्तविक रिकॉर्ड है। छात्रा ने दावा किया कि उसने सभी प्रश्न हल किए थे, लेकिन कोर्ट ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। दरअसल, सारागढ़ बिलाईगढ़ की 21 वर्षीय पीहू सिंह ने 21 जून 2026 को परीक्षा दी थी। नीट-

यूजी में 159 अंक मिलने पर छात्रा ने ओएमआर शीट पर सवाल उठाए। हाई कोर्ट ने एनटीए को छात्रा की मूल ओएमआर शीट पेश करने का निर्देश दिया। 10 अगस्त को एनटीए के डिप्टी डायरेक्टर अनिल धीमान ने मूल ओएमआर शीट कोर्ट में प्रस्तुत की। कोर्ट ने पाया कि छात्रा के 159 अंक मूल ओएमआर में दर्ज उत्तरों के अनुसार हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि टेस्ट बुकलेट में दिए गए उत्तर मूल ओएमआर शीट का स्थान नहीं ले सकते। कोर्ट ने कहा कि केवल यह दावा कि छात्रा ने अधिक प्रश्न हल किए थे, मूल ओएमआर में दर्ज उत्तरों को बदलने का आधार नहीं हो सकता।

खेत में काम कर रहीं दो महिलाओं पर भालू का हमला, क्षेत्र में दहशत

कोरबा। कोरबा जिले के वनांचल क्षेत्र डीडासरई-देवपहरी में खेत की ओर गई दो महिलाओं पर भालू ने अचानक हमला कर दिया। हमले में दोनों महिलाएं घायल हो गईं। ग्रामीणों की मदद से उन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोरबा पहुंचाया गया, जहां उपचार के बाद उनकी हालत खरे से बाहर बताई जा रही है। घटना के बाद वन विभाग ने आसपास के इलाके में निगरानी बढ़ा दी है। मंगलवार को मूल्यारो बाई (50) और समारी बाई गांव से लगे खेतों में काम करने गई थीं। इसी दौरान जंगल की ओर से आए भालू ने अचानक दोनों महिलाओं को निशाना बना लिया। हमले में उनके शरीर के अलग-अलग हिस्सों में चोटें आईं। अचानक हुई घटना से महिलाएं घबरा गईं और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिलते ही वे मौके पर पहुंचे और दोनों महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चिकित्सकों ने उनका उपचार शुरू किया। डॉक्टरों के अनुसार दोनों की



हालत फिलहाल स्थिर है और उन्हें निगरानी में रखा गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ग्रामीणों से जानकारी ली। टीम भालू के आने की दिशा और उसके संभावित ठिकाने का पता लगाने में जुटी है। वनांचल क्षेत्र में भालू के हमले की खबर फैलने के बाद आसपास के गांवों में भी सतर्कता बढ़ गई है। जंगल और खेतों के आसपास रहने वाले ग्रामीणों में वन्यप्राणी को लेकर भय बना हुआ है। वन विभाग ने लोगों से जंगल और खेतों की ओर अकेले नहीं जाने की अपील की है। खासकर सुबह और शाम के समय अतिरिक्त सावधानी बरतने तथा बच्चों को जंगल की ओर न भेजने की सलाह दी गई है। विभाग ने कहा है कि यदि किसी ग्रामीण को भालू या कोई अन्य वन्यप्राणी दिखाई देता है तो उसके पास जाने या उसे घेरने के बजाय तत्काल वन विभाग को

सर्व शिक्षक संघ ने डीईओ को सौंपा मांग पत्र

जनगणना इयूटी के अवकाश इंद्राज से लेकर पदोन्नति तक उठाए लंबित मुद्दे

गरियाबंद। सर्व शिक्षक संघ जिला गरियाबंद ने शिक्षकों की विभिन्न लंबित समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर मंगलवार को जिला शिक्षा अधिकारी राजेश चंद्राकर को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष जितेंद्र कुमार साहू के नेतृत्व में पहुंचे संघ के प्रतिनिधिमेंडल ने शिक्षक हित से जुड़े मुद्दों पर जल्द कार्रवाई की मांग की। संघ ने ज्ञापन में बताया कि सहायक शिक्षक ई/टी संवर्ग की अंतिम वरिष्ठता सूची अब तक जारी नहीं की गई है। कार्यालय द्वारा 10 जून 2026 को जारी पत्र के अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची जारी कर विकासखंड शिक्षा अधिकारियों से 18 जून तक प्रतिवेदन मांगा गया था। इसके बावजूद करीब दो माह बीत जाने के बाद भी अंतिम वरिष्ठता सूची जारी नहीं हो सकी है। संघ का कहना है कि अंतिम वरिष्ठता सूची जारी होने के बाद ही पदोन्नति की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी, ऐसे में इसमें हो रही देरी से शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में मुख्यमंत्री शिक्षक गौरव अलंकरण सम्मान समारोह 2025 का आयोजन गरियाबंद जिले में शीघ्र करने की मांग भी की गई। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के कई अन्य जिलों में यह सम्मान समारोह आयोजित हो चुका है, लेकिन गरियाबंद में पिछले वर्ष का शिक्षक सम्मान कार्यक्रम अब तक नहीं हो सका है।

संघ के अनुसार विकासखंडों से सम्मान के लिए प्रस्ताव जिला कार्यालय को भेजे जा चुके हैं, इसके बावजूद समारोह के आयोजन का लेक अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। शिक्षकों ने लंबित सम्मान समारोह जल्द आयोजित करने की मांग की है। शिक्षक संघ ने विभागीय परीक्षा में शामिल होने के लिए अनुमति समय पर नहीं मिलने की समस्या



भी छुश्रह के सामने रखी। इसके अलावा प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति प्रक्रिया लंबित होने और विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में शिक्षकों की सेवा पुस्तिका में अर्जित शैक्षणिक योग्यता का इंद्राज नहीं किए जाने का मुद्दा भी उठाया गया। संघ ने कहा कि सेवा पुस्तिका में शैक्षणिक योग्यता का समय पर इंद्राज नहीं होने से शिक्षकों को विभागीय कार्य और भविष्य में मिलने वाले लाभों में दिक्रतों का सामना करना पड़ सकता है। ज्ञापन में जनगणना इयूटी में लगाए गए शिक्षकों के अर्जित अवकाश का सेवा पुस्तिका में संधारण नहीं किए जाने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। संघ ने मांग की कि जनगणना इयूटी करने वाले सभी पात्र शिक्षकों के अर्जित अवकाश का नियमानुसार सेवा पुस्तिका में इंद्राज कराया जाए, ताकि उन्हें इसका लाभ मिल सके। संघ ने एकल शिक्षकीय विद्यालयों में अतिशेष शिक्षकों की वरिष्ठता के आधार पर स्थायी पदस्थापना किए जाने की मांग भी रखी। इसके साथ ही विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए सेवा प्रदाता शिक्षकों की व्यवस्था करने की मांग की गई, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो।सर्व शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष जितेंद्र कुमार साहू ने कहा कि शिक्षकों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामले लंबे समय से लंबित हैं। संघ ने जिला शिक्षा अधिकारी से इन समस्याओं का जल्द निराकरण करने का आग्रह किया है।

प्रयागराज से विशाखापट्टनम के लिए 16 फेरे लगाएगी स्पेशल ट्रेन



बिलासपुर। बिलासपुर से प्रयागराज और विशाखापट्टनम के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रेलवे ने अतिरिक्त यात्री दबाव को देखते हुए दोनों शहरों के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त रेल सेवा और बर्थ का विकल्प मिल सकेगा। यात्रियों की बढ़ती संख्या और ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने प्रयागराज और विशाखापट्टनम के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। दोनों दिशाओं में यह ट्रेन 16-16 फेरे लगाएगी। इस सेवा से प्रयागराज, बिलासपुर, रायगढ़ समेत मार्ग के अन्य स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी। गाड़ी संख्या 04159

प्र यागराज-विशाखापट्टनम साप्ताहिक स्पेशल 14 अगस्त से 27 नवंबर 2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को प्रयागराज से रवाना होगी। यह ट्रेन शहडोल, अनूपपुर, पेंड्रारोड, बिलासपुर और रायगढ़ सहित विभिन्न स्टेशनों से होकर विशाखापट्टनम पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04160 विशाखापट्टनम-प्रयागराज साप्ताहिक स्पेशल 15 अगस्त से 28 नवंबर 2026 तक प्रत्येक शनिवार को संचालित होगी।

प्रयागराज से विशाखापट्टनम जाने वाली ट्रेन बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर रात 10.15 बजे पहुंचेगी और 10.25 बजे रवाना होगी। वहीं विशाखापट्टनम से प्रयागराज जाने वाली स्पेशल ट्रेन बिलासपुर में सुबह 6 बजे पहुंचेगी और 6.10 बजे रवाना होगी। इसके अलावा शहडोल,

अनूपपुर और पेंड्रारोड समेत मार्ग के कई प्रमुख स्टेशनों पर भी दोनों दिशाओं में ट्रेन का ठहराव रहेगा। रेलवे के अनुसार स्पेशल ट्रेन में कुल 22 कोच लगाए जाएंगे। इनमें पांच जनरल, सात स्लीपर, एक एसी-2, चार एसी-3, तीन एसी-3 इकोनॉमी, एक पावर कार और एक एसएलआरडी कोच शामिल हैं। अलग-अलग श्रेणी के कोच होने से यात्रियों को अपनी सुविधा और बजट के अनुसार यात्रा का विकल्प मिलेगा। प्रयागराज और विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली यह ट्रेन मानिकपुर, सतना, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, पेंड्रारोड, बिलासपुर, रायगढ़, झारसुगुड़ा रोड, संबलपुर, बलांगीर, टटिलागढ़ और विजयनगरम सहित कई स्टेशनों पर ठहरेगी। त्योहारी और व्यस्त यात्रा अवधि के दौरान ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए शुरू की जा रही इस स्पेशल सेवा से यात्रियों को अतिरिक्त बर्थ और यात्रा का विकल्प मिलेगा। रेलवे की इस व्यवस्था से प्रयागराज और विशाखापट्टनम के बीच सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

निजी स्कूलों में पाठ्यपुस्तक वितरण में लापरवाही

बिलासपुर। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने निजी स्कूलों के द्वारा शासन की ओर से उपलब्ध कराई जा रही पाठ्यपुस्तकों का उठाव नहीं होने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। कलेक्टर ने संबंधित निजी स्कूल प्रबंधनों को शो-काॅज नोटिस जारी करने और जवाब के साथ जिला कलेक्टोरेट में विशेष बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने ये निर्देश मंगलवार को जिला कलेक्टोरेट में आयोजित साप्ताहिक टीएल बैठक में दिए। कलेक्टर के साथ हुई बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने कहा कि विद्यार्थियों को समय पर पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। शासकीय स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों एवं गणवेश वितरण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, ऐसे में निजी स्कूलों द्वारा पुस्तकों का उठाव नहीं किया जाना गंभीर विषय है। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को इसकी निगरानी करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

छग संस्कृति की थीम पर तैयार हो रहीं इको-फॅडली राखियां

कोरबा। रक्षाबंधन को लेकर पर्यावरण संरक्षण और वोकल फॉर लोकल का संदेश कटघोरा विकासखंड में झलक रहा है। धवईपुर में महिला स्व-सहायता समूह की महिलाएं इस साल खास किस्म की राखियां तैयार कर रही हैं। इको-फॅडली और स्वदेशी राखियों का निर्माण किया जा रहा है जो बाजार में आकर्षण का मुख्य केंद्र हैं। इन राखियों की न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि धूव-दराज के बाजारों में भी अच्छी डिमांड है। धवईपुर की महिलाओं ने पूरी तरह प्रकृतिक और जैविक सामग्रियों से राखियां तैयार की हैं। इन राखियों के निर्माण में किसी भी प्रकार के प्लास्टिक या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले सामग्रियों का उपयोग नहीं किया है। इन राखियों को बनाने में मुख्य रूप से रुद्राक्ष और कौड़ी का उपयोग किया गया है। जो लोगों को पारंपरिक और आध्यात्मिक महत्व को जोड़ने का काम करता है। रक्षा सूत्र के पारंपरिक प्रतीक के रूप में मौली धागा सहित धान, चावल और दाल को अन्नपूर्णा के आशीर्वाद और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता दर्शाने के संदेश से उपयोग में लाया गया।

जांजगीर चांपा से भेजा गया रक्षाबंधन का विशेष तोहफा

जांजगीर चांपा। फौजी भाइयों के लिए जांजगीर चांपा जिला से हर साल की तरह इस बार भी राखी भेजी जा रही है। राखी भेजने के लिए चाम्पा के शहीद चौक में खास कार्यक्रम हुआ। महिला संगठनों ने पुलिस अधीक्षक और सेना के जवानों को राखी बांधा और अपने हाथों से बनाई 25 हजार राखियों को ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र के वाहन में दिल्ली के लिए रवाना किया। दरअसल पूर्व सैनिकों ने देश भर की राखी एकत्र कर दिल्ली पहुंचाने का जिम्मा उठाया है। 23 अगस्त से पहले दिल्ली पहुंचाने की योजना बनाई है। पूर्व सैनिक संगठन ने देश भर की महिलाओं के साथ मिल कर चार साल पहले राखी सेना के जवानों तक पहुंचाने की शुरुआत की थी। अब इस मुहिम से देश भर की बहनें जुड़ कर भारी तादात में राखी सैनिक भाइयों के लिए भेजती हैं। ऑपरेशन रक्षा सूत्र को चार साल हो गए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ से राखी इकट्ठा की जाती है। हबल, गोबर, धान समेत कई तरह की राखियां महिला समूह बनाती है। इन सभी राखियों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। ये रायपुर भेजी जाएगी।

बीएसपी में नौकरी का झांसा, लाखों रुपए की ठगी

दुर्ग। बीएसपी यानी भिलाई इस्पात संयंत्र में लोको पायलट के पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को उर्दा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।आरोपी ने फर्जी तरीके से खुद को नौकरी लगवाने में सक्षम बताकर कई युवाओं को अपना शिकार बनाया था। एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि पीड़ित दीपक कुमार देवदास ने थाना उर्दाई में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी।इससे बताया कि आरोपी चंद्रप्रकाश साहू ने प्रार्थी समेत करीब 15 युवाओं से बीएसपी में नौकरी लगाने की बात कही थी।चंद्रप्रकाश ने लोगों को लोको पायलट बनाने का भरोसा दिया था। झांसे में आगरेज प्रार्थी ने आरोपी को कुल पांच लाख तीस हजार रुपए दे दिए। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब नौकरी नहीं लगी, तो प्रार्थी ने अपनी रकम वापस मांगी। इस पर आरोपी लगातार टालमटोल करने लगा और पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी का बैंक खाता और मोबाइल फोन जब्त कर लिया है।

कांकेर में रिहायशी इलाकों में लगातार पहुंच रहे भालू

कांकेर। जिले में जंगली जानवरों की बढ़ती आवाजाही ने ग्रामीणों के साथ शहर से लगे इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों से घिरे कांकेर में भालू, तेंदुए समेत दूसरे वन्यजीव लगातार रिहायशी इलाकों के करीब पहुंच रहे हैं। इससे लोगों में डर का माहौल है और वन विभाग से सुरक्षा देने की मांग की जा रही है। हाल के दिनों में भालू के हमले में दो ग्रामीणों की मौत और एक व्यक्ति के घायल होने के बाद लोगों में नाराजगी भी बढ़ी है। ग्रामीणों का कहना है कि वन्यजीवों की आबादी वाले क्षेत्रों में बढ़ती आवाजाही को रोकने और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने की जरूरत है। दरअसल, कांकेर जिला जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है। यहां भालू, तेंदुए और कई दूसरे वन्यजीवों का प्राकृतिक ठिकाना है। जंगल से लगे गांवों में वन्यजीवों का आना पहले भी होता रहा है, लेकिन अब इनके रिहायशी इलाकों तक पहुंचने की घटनाएं ज्यादा सामने आ रही हैं।

सीईओ ने झलप में पीएम सूर्य घर योजना का किया निरीक्षण

महासमुंद। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री अनुपमा आनंद ने महासमुंद विकासखंड अंतर्गत ग्राम झलप का दौरा कर पीएम सूर्य घर योजना की प्रगति का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के तहत महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा संचालित आजीविका गतिविधियों और स्व-निर्मित उत्पादों का अवलोकन किया। सीईओ ने वात्सल्य महिला क्लस्टर संगठन, झलप के अंतर्गत वेंडर के रूप में कार्य कर रही सोलर दीदी काजल साहू के घर पहुंचकर पीएम सूर्य घर योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। प्रशिक्षण



प्राप्त कर काजल साहू ने अपने निवास पर 2 किलोवाट का सोलर पैनल स्थापित किया है। सीईओ सुश्री अनुपमा आनंद ने उनके कार्य की सराहना करते हुए अधिक से अधिक लोगों को सौर ऊर्जा से जोड़ने तथा सोलर पैनल स्थापना के कार्य को विस्तार देने

के लिए प्रोत्साहित किया। भ्रमण के दौरान सीईओ ने बिहान के जय भवानी स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित दुकानों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे बाँस की हस्तकला सामग्री, अचार, बड़ी, पापड़, मसाले सहित

विभिन्न स्व-निर्मित उत्पादों का अवलोकन किया। उन्होंने महिलाओं से संवाद कर उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने, बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और आजीविका गतिविधियों को और अधिक विस्तारित करने के संबंध में मार्गदर्शन दिया। सुश्री आनंद ने बिहान समूह की महिलाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि अपने उत्पादों का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें और नए बाजारों से जुड़कर आय के साधनों को बढ़ाएं। इस अवसर पर जिले से एपीओ त्रिवेणी, डीपीएम शिवदे सिंह सहित क्लस्टर संगठन की पदाधिकारी बहनें एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग पर डॉक्टरों का अनोखा प्रदर्शन

जगदलपुर। जगदलपुर स्थित मेडिकल कॉलेज डिमरापाल के इंटरन चिकित्सक स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले आठ दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। सरकार से लगातार मांग रखने के बावजूद समाधान नहीं होने पर अब डॉक्टरों ने अनोखे तरीके से अपनी आवाज उठाई है। मंगलवार शाम इंटरन चिकित्सकों ने शहर में पैदल मार्च निकाला और बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के मंदिर पहुंचकर अपनी मांगों से जुड़ी अर्जी देवी को अर्पित की। इंटरन चिकित्सकों की प्रमुख मांग मासिक स्टाइपेंड को 15,900 रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये करने की है। चिकित्सकों का कहना है कि इस संबंध में सरकार को पत्र और कई बार निवेदन किया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। मांग पूरी नहीं होने के बाद इंटरन डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। मेडिकल कॉलेज परिसर में



चिकित्सक धरने पर बैठे हैं और तालपत्री लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में इंटरन और पीजी रेजिडेंट डॉक्टरों को दूसरे राज्यों की तुलना में काफी कम स्टाइपेंड मिल रहा है। इंटरन डॉक्टरों के साथ पीजी रेजिडेंट भी स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग उठा रहे हैं। चिकित्सकों के अनुसार छत्तीसगढ़ में पीजी प्रथम वर्ष का स्टाइपेंड करीब 67,500 रुपये है, जिसे वे अन्य राज्यों की तुलना में कम बता रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे चिकित्सकों का कहना है कि लंबे समय तक प्रशिक्षण और अस्पतालों में जिम्मेदारी के साथ सेवाएं देने वाले इंटरन और

पीजी डॉक्टरों को उनके काम के अनुरूप सम्मानजनक स्टाइपेंड मिलना चाहिए। उन्होंने समय पर स्टाइपेंड भुगतान और चिकित्सकों के हित में उचित व्यवस्था की मांग की है। हड़ताल के आठवें दिन मंगलवार शाम इंटरन चिकित्सकों ने अपनी मांगों के समर्थन में पैदल मार्च निकाला। मार्च चांदनी चौक से शुरू होकर शहीद पार्क, पुराना बस स्टैंड, मेन रोड, गोल बाजार और सिरहासार होते हुए मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचा। मंदिर पहुंचने के बाद चिकित्सकों ने मां दंतेश्वरी को अपनी मांगों और समस्याओं से संबंधित पत्र सौंपा। डॉक्टरों ने प्रार्थना करते हुए सरकार तक उनकी आवाज पहुंचने और जल्द मांग पूरी होने की कामना की। इंटरन चिकित्सकों का कहना है कि वे अपनी मांग को लेकर पहले ही शासन-प्रशासन के समक्ष पक्ष रख चुके हैं। इसके बावजूद समाधान नहीं होने के कारण आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा।

संक्षिप्त समाचार

हरेली तिहार पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने प्रदेश के प्रथम लोकपर्व हरेली तिहार के पावन अवसर पर समस्त छत्तीसगढ़वासियों को गाड़ा-गाड़ा बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मंत्री श्री चौधरी ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि हरेली छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोकसंस्कृति, कृषि परंपरा और प्रकृति के प्रति कुतज्ञता का पर्व है। यह पर्व किसानों के जीवन में विशेष

महत्व रखता है और खेती-किसानी में उपयोग होने वाले कृषि औजारों एवं पशुधन की पूजा के माध्यम से अन्नदाता के प्रति सम्मान की भावना को अभिव्यक्त करता है। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि हरेली का पावन पर्व प्रदेश में हरियाली, सुख-समृद्धि और खुशहाली का संदेश लेकर आता है। उन्होंने कामना की कि भगवान सभी किसान भाई-बहनों के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली प्रदान करें तथा उनकी मेहनत से खेत-खलिहान सदैव लहलहाते रहें।

स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति पदक से बिलासपुर आईजी होंगे सम्मानित

रायपुर। राजधानी रायपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिलासपुर आईजी रामगोपाल गर्ग को पुलिस महकमें में उत्कृष्ट सेवाओं और बेहतर कार्य करने पर राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। 18 साल की सेवा में

गर्ग ने अपनी बेहतर कार्यप्रणाली और सख्त पुलिसिंग के बदौलत महकमे में एक विशिष्ट पहचान बनाई है। गर्ग को उनकी कर्तव्यपरायणता और ईमानदार छवि की वजह से जाना जाता है। 2007 बैच के आईपीएस श्री गर्ग गरियाबंद, कोरिया, बालोद व दुर्ग में बतौर एसपी सेवाएं दीं। वह सरगुजा और दुर्ग आईजी के पद पर कार्य करने के पश्चात बिलासपुर में इसी पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले वह डीआईजी रायगढ़ के पद पर भी रहे। करीब 7 वर्षों तक सीबीआई में वह पदस्थ रहे। गर्ग सदैव बुनियादी पुलिसिंग के पक्षधर रहे हैं। वह समय-समय पर पुलिस को जमीनी स्तर पर मजबूती देने के इरादे से कार्यशाला और अन्य तकनीकी कार्यों को बेहतर रूप देने पर जोर देते रहे हैं। गर्ग को राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ कार्यों के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने अपने सर्विस कैरियर में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भी ऐग भी तैयार किया। उनके अनुभव और अच्छे कार्यों के चलते केंद्र सरकार ने उन्हें इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया में भी ट्रेनिंग के लिए भेजा था। इस बीच केंद्र सरकार ने उन्हें राष्ट्रपति पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है। इसी के चलते राजधानी रायपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्हें राष्ट्रपति मेडल से नवाजा जाएगा।

राष्ट्रपति भवन में गूंजेगी छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के नगरी की मांदर की थाप

रायपुर। 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश की राजधानी नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में छत्तीसगढ़ की समृद्ध आदिवासी लोककला, संस्कृति और परंपराओं के लिए यह गौरव का क्षण है। छत्तीसगढ़ के जिले के नगरी विकासखंड की पारंपरिक लोककला की अनूठी छटा देखने को मिलेगी। ग्राम सरईटोला (गुडरापार) का सुप्रसिद्ध ‘जय गढ़िया बाबा आदिवासी लोक मांदरी नृत्य दल’ राष्ट्रपति भवन में छत्तीसगढ़ की पारंपरिक गुट्टा मांदर नृत्य की रंगारंग प्रस्तुति देगा। यह अवसर न केवल छत्तीसगढ़ सहित धमतरी जिले के लिए गौरव का विषय है। देश के ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित मंच पर जिले के ग्रामीण अंचल के कलाकारों को अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर मिलना प्रदेश की लोक परंपराओं की राष्ट्रीय पहचान की और मजबूत करेगा। सरईटोला का यह लोक नृत्य दल अपनी विशिष्ट गढ़वा नृत्य शैली, गुट्टा मांदर की ऊर्जावान प्रस्तुति, पारंपरिक वेशभूषा और लोक वाद्यों के लिए जाना जाता है। दल के कलाकार अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज के लोकजीवन, परंपराओं, उत्सवों और सामुदायिक संस्कृति की जीवंत झलक प्रस्तुत करते हैं। मांदर की थाप, पारंपरिक गीत और सामूहिक नृत्य की लय इस कला को विशिष्ट पहचान प्रदान करती है।

रामलला दर्शन के लिए राजनांदगांव से अयोध्या धाम रवाना हुई विशेष ट्रेन

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेशवासियों की धार्मिक आस्था और भावनाओं को सम्मान देते हुए संचालित रामलला दर्शन योजना प्रदेश के श्रद्धालुओं को प्रभु श्रीराम की पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है। योजना के अंतर्गत अब तक 50 हजार से अधिक श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर चुके हैं। इसी क्रम में आज राजनांदगांव से रामलला दर्शन विशेष ट्रेन श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई। इस अवसर पर स्टेशन परिसर जय श्रीराम के जयघोष से गूंज उठा और श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री श्री राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में योजना के माध्यम से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ प्रदेश के श्रद्धालुओं को देश के प्रमुख तीर्थस्थलों से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष ट्रेनों के माध्यम से समूह में तीर्थयात्रा की सुविधा मिलने से श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या धाम की यात्रा अधिक सहज, व्यवस्थित और सुविधाजनक बन रही है। रामलला दर्शन योजना के तहत अब तक 50 हजार से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम पहुंचकर प्रभु श्रीराम के दर्शन कर चुके हैं। यह उपलब्धि प्रदेशवासियों की रामलला के प्रति गहरी आस्था के साथ ही योजना की व्यापक स्वीकार्यता को दर्शाती है।

राजधानी/छत्तीसगढ़

हरेली पर्व पर मुख्यमंत्री निवास में सजी लोक संस्कृति की जीवंत झांकी

गेड़ी, बिल्लस, गोटी और बाटी जैसे पारंपरिक खेलों ने लौटाई गांव की यादें

रायपुर। छत्तीसगढ़ की लोक परंपराओं, कृषि संस्कृति और ग्रामीण जीवन की आत्मा माने जाने वाले प्रथम पर्व हरेली का भव्य और सांस्कृतिक गरिमा से भरपूर आयोजन नया रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में उत्साहपूर्वक किया गया। आयोजन ने राजधानी में छत्तीसगढ़ के गांवों की सौंधी खुशबू और पारंपरिक जीवन शैली को साकार कर दिया।

मुख्यमंत्री निवास परिसर को नीम और आम के पत्तों, गेंदे के फूलों तथा पारंपरिक ग्रामीण सजावट नया रायपुर रूप से सजाया गया था। प्रवेश द्वार से लेकर मुख्य परिसर तक छत्तीसगढ़ी संस्कृति की झलक दिखाई दे रही थी। हरियाली, प्राकृतिक सजावट और लोक अलंकरण ने पूरे वातावरण को उत्सवमय बना दिया।

हरेली पर्व के अवसर पर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों का विशेष आकर्षण देखने को मिला। गेड़ी दौड़ ने लोगों में रोमांच और उत्साह भर दिया, वहीं बिल्लस, गोटी और बाटी जैसे ग्रामीण खेलों ने बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। इन खेलों के माध्यम से नई पीढ़ी को छत्तीसगढ़ की पारंपरिक खेल संस्कृति से परिचित कराने का संदेश भी दिया गया।



आयोजन में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजनों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। टेउरी, खुरमी, बड़ा सहित अनेक पारंपरिक पकवानों का स्वाद लोगों ने उत्साहपूर्वक लिया। ग्रामीण अंचलों में विशेष अवसरों पर बनाए जाने वाले इन व्यंजनों ने लोगों को अपने गांव और पारिवारिक उत्सवों की याद दिला दी।

लोक कलाकारों ने छत्तीसगढ़ी लोकगीत और लोकनृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां देकर पूरे आयोजन को जीवंत बना दिया। मांदर, ढोलक और पारंपरिक वाद्ययंत्रों की थाप पर कलाकार झुमेते नजर आए। लोकधुनों पर उपस्थित जनसमूह भी तालियां बजाते और उत्साह से सहभागी बनते दिखाई दिए। आयोजन में छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विविधता और लोक कला की समृद्ध परंपरा का प्रभावशाली प्रदर्शन हुआ।

कार्यक्रम का एक विशेष आकर्षण रहचुली रहा, जिसका आनंद बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ने लिया। ग्रामीण मेलों और पारंपरिक उत्सवों की पहचान मानी जाने वाली रहचुली ने आयोजन में गांव के मेले जैसा आनंदमय वातावरण बना

दिया।

हरेली पर्व मूलतः कृषि और प्रकृति से जुड़ा उत्सव है। इस दिन किसान अपने कृषि औजारों की पूजा कर अच्छी फसल और समृद्धि की कामना करते हैं। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित इस कार्यक्रम ने हरेली को केवल एक पर्व नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की लोक अस्मिता, कृषि परंपरा और सांस्कृतिक गौरव के उत्सव के रूप में प्रस्तुत किया।

नया रायपुर में आयोजित यह भव्य आयोजन इस बात का प्रतीक बना कि छत्तीसगढ़ अपनी आधुनिक विकास यात्रा के साथ-साथ अपनी लोक संस्कृति, पारंपरिक खेलों, खानपान और ग्रामीण विरासत को भी समान सम्मान और संरक्षण दे रहा है। हरेली महोत्सव ने राजधानी में उपस्थित लोगों को छत्तीसगढ़ की मिट्टी, हरियाली और

बरस्तर तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप

■ 13 अगस्त को सुकमा के दुर्गम इलाकों से गुजरेगी तिरंगा यात्रा

रायपुर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बस्तर अंचल में राष्ट्रभक्ति, शांति और विकास का संदेश लेकर ‘बस्तर तिरंगा यात्रा 2026’ का आयोजन किया जा रहा है। 13 अगस्त को सुकमा जिले में होने वाली इस तिरंगा यात्रा में उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा और वन एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप भी शामिल होंगे। मोटरसाइकिलों के माध्यम से आयोजित यह यात्रा बस्तर के उन गांवों और क्षेत्रों तक पहुंचेगी, जो कभी नक्सल और क्षेत्रों तक पहुंचेगी, जो कभी नक्सल हिंसा से प्रभावित थे और अब शांति, सुरक्षा और विकास की नई राह पर आगे बढ़ रहे हैं। ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत इस यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना को जन-जन तक पहुंचाना है।



13 अगस्त को तिरंगा यात्रा चिंगावर्म, सुकमा, एर्राबोर, मनीकोंटा, दोरनापाल, पोलमपल्ली, बुर्कापाल, मिनापा-टाइमेटला, चिंतलनार, जगरगुंडा, सिलगेर और टेकलगुडुम होते हुए आवापल्ली और बीजापुर पहुंचेगी। बीजापुर में रात्रि विश्राम किया जाएगा।

यात्रा का उद्देश्य बस्तर की बदलती तस्वीर को देश-दुनिया के सामने लाना, युवाओं को राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा से

नारायणपुर से शुरु हुई बस्तर तिरंगा यात्रा

रायपुर। बस्तर में शांति, एकता और राष्ट्र निर्माण का संदेश लेकर बुधवार को नारायणपुर जिला मुख्यालय के हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड से %बस्तर तिरंगा यात्रा 2026% का शुभारंभ हुआ। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा एवं वन मंत्री श्री केदार कश्यप बाइक पर तिरंगा लेकर यात्रा का नेतृत्व करते हुए रवाना हुए, जिसे क्षेत्र के विभिन्न समाज प्रमुखों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बस्तर तिरंगा यात्रा के आयोजन में शामिल बच्चों से मंत्री द्वय ने उनके बीच पहुंच कर आत्मीयता के साथ मुलाकात की और सभी का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर उन्होंने विकास का बिगुल फूंकते हुए सभी को शांति और विकास का संदेश दिया। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि यह यात्रा उन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी, जहां पहले नक्सली घटनाओं ने लोगों को प्रभावित किया था। उन्होंने कहा कि यात्रा के माध्यम से देश और दुनिया को यह संदेश दिया जाएगा कि इन क्षेत्रों में अब नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। उन्होंने बताया कि नारायणपुर का चयन विशेष उद्देश्य के तहत किया गया है, क्योंकि यह जिला सबसे लंबे समय तक नक्सल प्रभावित रहा है। यात्रा का

समापन 14 अगस्त को बीजापुर जिले के करेंगुट्टा पहाड़ी पर तिरंगा फहराकर किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में माओवाद के विरुद्ध नीति बनाकर नियत तिथि पर 31 मार्च 2026 में नक्सलवाद राज्य के साथ साथ देश से समाप्त किया गया है। आज के बाद हर राष्ट्रीय पर्व एवं स्वतंत्रता दिवस पर बस्तर के कोने-कोने तक भारत का तिरंगा पूरी आन, बान और शान से लहराएगा। उन्होंने कहा कि जनवरी 2024 से लेकर अब तक बस्तर के अनेक दुर्गम गाँवों में लगातार राष्ट्रीय पर्वों पर ध्वजारोहण किया गया है। इस स्वतंत्रता दिवस पर बस्तर सभाग के 90 से अधिक ऐसे गाँव हैं, जहाँ आजादी के बाद पहली बार इस स्वाधीनता दिवस पर तिरंगा लहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि तिरंगा फहरने का मतलब बाबा साहब के द्वारा लिखा संविधान अब राज्य के कोने कोने पर लागू होगा। श्री शर्मा ने कहा कि आज जब मैं बस्तर के अलग अलग गांवों में जाता हूँ तो बस्तरवासी कहते हैं कि वे खुद को सही मायनों में स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं।

भाजपा सरकार में हुआ जघन्य झीरम कांड, जनता से माफी मांगकर करें प्राथश्चित : दीपक बैज

रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी नेताओं से झीरम कांड के लिए जनता से माफी मांगने की बात कही है। दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी नेताओं को उन शहीद कांग्रेस नेताओं से भी माफी मांगनी चाहिए जो इस कांड का शिकार बने। छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है।इनके पास राजनीति के लिए ना तो कोई मुद्दे बचे हैं और ना ही जनता का भरोसा। बीजेपी लगातार जनता के भीतर अपना विश्वास खोते जा रही हैं और यही वजह है कि इनके नेता अब अनर्गल बयान देते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री तिरंगा यात्रा में झीरम जा रहे हैं उन्हें जाना भी चाहिए और झीरम कांड को लेकर उन्हें प्रायश्चित भी करना चाहिए। दीपक बैज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जनता से झूठ बोल रही है। इनके



पास काम करने के लिए कुछ बचा नहीं है।भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार झूठ बोल रही है और जनता को गलत जानकारी दे रही है।

पंचायती राज मंत्री विजय शर्मा को लेकर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में गरीबों के घर बनाने के मामले को लेकर विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा कि 18 लाख घर बना दिए गए हैं। लेकिन यह कितना झूठ बोलते हैं इसका पूरा ब्यौरा संसद में साफ-साफ सामने आ गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सांसद बुजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में 10

लाख के आसपास ही घर बने हैं। सबसे महत्वपूर्ण मामला यह है कि झूठ बोल कौन रहा है।

दीपक बैज ने कहा विजय शर्मा कहते हैं कि 18 लाख घर बन गया है।सांसद बुजमोहन अग्रवाल कहते हैं अभी 10 लाख घर भी नहीं बना है। आखिर जनता को इस तरह से झूठी जानकारी देना और पूरे छत्तीसगढ़ को झूठ के आधार पर चीजों को बताना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदत बन गई है। इनकी कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर है।

छत्तीसगढ़ में अपराध अनियंत्रित हो गया है चाहे हत्या का मामला हो या फिर नशा के कारोबार का मामला हो। इस पूरे मामले पर छत्तीसगढ़ सरकार का नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो चुका है।विधि व्यवस्था के मामले को लेकर कांग्रेस की सरकार एक बड़ा आंदोलन करेगी और इसकी पूरी रणनीति हम लोग तैयार कर रहे हैं।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग (भ/स) अम्बिकापुर मण्डल अम्बिकापुर निविदा आमंत्रण तिथि - 10.08.2026			
ई-प्रोक्चोरमेंट निविदा सूचना			
01. निविदा की विस्तृत जानकारी के लिये Log in करें http://eproc.cgstate.gov.in			
02. संबंधित निविदा-स.क्र. 01 से 4 पथदलागांव एवं स.क्र. 5,6 जशपुर संभाग			
03. स.क्र. 01 से 6 'द' वर्ग एवं ऊपर ठेकेदार			
04. अनंतिमाला निविदा बनाने की अंतिम तिथि-स.क्र. 1 21.08.2026 स.क्र. 2 से 4 01.09.2026 एवं स.क्र. 5, 6 27.08.2026			
सरल क्र.	एन.आई.टी. क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)
1	2	3	4
1	132	लोक निर्माण विभाग उपसंभाग क्र. 1 पथलगांव के अंतर्गत विभिन्न ग्रामीण मार्गों में डब्ल्यू.एम.एम., इमलशन, बी.टी. चैच रिपेयर का कार्य। (द्वितीय आमंत्रण)	25.00
2	133	जिला जशपुर फरसाबहार में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सह कृषि आदान सामग्री	54.02
3	134	गोदाम हेतु नवीन भवन का निर्माण कार्य। (प्रथम आमंत्रण)	54.02
4	135	जिला जशपुर पथलगांव में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सह कृषि आदान सामग्री गोदाम हेतु नवीन भवन का निर्माण कार्य। (प्रथम आमंत्रण)	49.38
5	136	लोक निर्माण विभाग संभाग जशपुर के अंतर्गत विभिन्न मार्गों में इमलशन बी.टी. चैच रिपेयर का कार्य। (द्वितीय आमंत्रण)	20.00
6	137	लोक निर्माण विभाग संभाग जशपुर अंतर्गत विभिन्न मार्गों में डब्ल्यू.एम.एम. एवं इमलशन चैच रिपेयर का कार्य। (द्वितीय आमंत्रण)	50.00
अधीक्षण अभियंता			
जौ-262702725 /7			लोक निर्माण विभाग,अम्बिकापुर, मण्डल अम्बिकापुर

कांग्रेस के पास राहुल गांधी के अलावा विकल्प नहीं!

हरिश गुप्ता

कोई भी अन्य विकल्प नहीं है। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि अब यह टीना (देयर इज नो अल्टरनेटिव) फैक्टर ही राहुल गांधी के प्रति पार्टी के रवैये को आकार दे रहा है। बंद दरवाजों के पीछे आलोचनाओं की कोई कमी नहीं है। वरिष्ठ नेता निजी तौर पर स्वीकार करते हैं कि राहुल के बिना तैयारी के दिए गए भाषणों से उन्हें अक्सर असहजता होती है। उनका मानना है कि उनके भाषण, विशेष रूप से बिना सोचे-समझे की गई टिप्पणियां, कभी-कभी भाजपा को नरैटिव को अपने नियंत्रण में लेने का मौका दे देती हैं। मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, बहस अक्सर इस बात पर केंद्रित हो जाती है कि राहुल ने क्या कहा – या उनके द्वारा कही गई मानी जाने वाली बातें क्या थीं। कई लोगों का मानना है कि बेहतर तैयारी और तेज-तर्रार संदेशों से वह कहीं अधिक मजबूत प्रतिद्वंद्वी बन सकते हैं। फिर भी, आलोचना वहीं खत्म हो जाती है जहां नेतृत्व का प्रश्न शुरू होता है। कांग्रेस के सामने कड़वा सच यह है कि कोई नेता राहुल गांधी के आसपास भी नहीं है। महत्किर्जुन खरगे सम्मान के पात्र हैं, लेकिन पार्टी के जन प्रचारक नहीं हैं। युवा पीढ़ी के नेताओं को अभी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल करनी बाकी है। क्षेत्रीय नेताओं का अपने-अपने राज्यों में प्रभाव है, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर उनकी स्वीकार्यता नहीं है। यहां तक कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल भी, राहुल गांधी से कभी-कभार मतभेद होने के बावजूद, विपक्ष को जब भी किसी राष्ट्रीय चेहरे की जरूरत होती है, तो स्वाभाविक रूप से उनकी ओर देखते हैं। इससे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसे कांग्रेस के एक रणनीतिकार ने पार्टी का टीना फैक्टर बताया है। पार्टी के भीतर चर्चा इस बात पर केंद्रित है कि उन्हें अनावश्यक राजनीतिक संकटों से कैसे बचाया जाए और उनकी बढ़ती राजनीतिक आक्रामकता को चुनावी लाभ में कैसे बदला जाए। तमाम कानाफूसी, निराशाओं और निजी सलाहों के बावजूद, कांग्रेस ने चुपचाप उस राजनीतिक वास्तविकता को स्वीकार कर लिया है जो भाजपा के नजरिये से मेल खाती है। जिस प्रकार भाजपा नरेंद्र मोदी को अजेय और उनके करिश्मे को बरकरार मानती है, उसी प्रकार कांग्रेस भी इस निष्कर्ष पर पहुंच गई है कि अच्छा हो या बुरा, राहुल गांधी का कोई विकल्प नहीं है। भारतीय राजनीति में बहुत कम नेता ऐसे हैं जिनका अपने परिवार से इतना गहरा जुड़ाव हो जितना राहुल गांधी का है। लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि लगातार परामर्श के बावजूद, राहुल के अंतिम निर्णय का अनुमान लगाना कभी आसान नहीं होता। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से परिचित करीबी पार्टी पदाधिकारियों के अनुसार, राहुल गांधी नियमित रूप से महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर अपने एक छोटे से समूह के साथ चर्चा करते हैं, जिसमें कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और कुछ विश्वसनीय सलाहकार शामिल हैं। इन मुलाकातों को देखने वालों का कहना है कि राहुल गांधी व्यक्तिगत बैठकों में ध्यान से सुनते हैं और अपना निर्णय लेने से पहले धैर्यपूर्वक अलग-अलग दृष्टिकोणों को समझते हैं। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो अंतिम क्षण तक अपने अंतिम विचार शायद ही कभी प्रकट करते हैं। यहां तक कि उनके सबसे करीबी लोग भी अक्सर अंतिम निर्णय का इंतजार करते रहते हैं। नतीजतन, पार्टी के भीतर अटकलें तब तक जारी रहती हैं जब तक कि औपचारिक रूप से निर्णय की घोषणा नहीं हो जाती। कुछ नेताओं का मानना है कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सलाह देते समय बहुत सावधानी बरतती हैं और दबाव के बजाय समझा-बुझाकर अपनी बात रखती हैं।

पुराण दिग्दर्शन

विश्व विद्या-निरुपणाध्यायः (दशम अध्याय)

(गतांक से आगे...)

इसके अतिरिक्त अमुक ग्रह, उपग्रह का परिमाण क्या है ? तथा वह पृथ्वी से कितनी दूर स्थित है ? एवं किस गति से कितने समय में किस मार्ग से घूमता है ? इत्यादि बात भी भलीभांति प्रकट की गई हैं।

खगोल-तत्त्ववेत्ता बहुत दिनों तक अनुसन्धान करने के बाद अभी अभी यह समझ सके हैं कि ग्रहों की गति विगति का प्रभाव पृथ्वी पर भी अवश्यमेव पड़ता है। अब तो कई गवेषक यहाँ तक स्पष्ट कहने लग पड़े हैं कि पुच्छलतारा निकलने से पुरुषों के स्वभाव तमोगुण के आवेश में ना जाते हैं और वे अकारण आपस में एक दूसरे के रुधिर के प्यासे बन जाते हैं।

यूरोपियन ज्योतिषियों ने मंगल का नाम ही मार्स (Mars) रक्खा है जो कि युद्ध-कालीन मार्शल (Marshal) शब्द से सम्बन्ध रखता है। मङ्गल या शनैश्चर की विशेष दशा में भी अब अनिष्ट फल का

होना माना जाना लगा है, परन्तु हिन्दूशास्त्रों का यह महत्त्व है कि हमारे पूर्वजों ने इन सब बातों को आज से सहस्रों वर्ष पूर्व न केवल जाना ही था बल्कि दृष्टग्रहों के प्रभाव से बचने के उपायों की भी खोज निकाला था, जिसका बुंधला किन्तु सत्यस्वरूप फलित ज्योतिष के रूप में अद्यावधि विद्यमान है।

खगोल का विषय यूं तो प्रायः सभी पुराणों में आया है, परन्तु कूर्मपुराण और भविष्यपुराण का वर्णन बड़ा ही मनोहर है। नवीन खगोलवेत्ता ग्रह उपग्रहों की दूरी के विषय में अभी तक कोई मत स्थिर नहीं कर सके, उनके मत अभी तक साध्यकोटि में ही समझने चाहियें।

उत्तरोत्तर विज्ञान ज्यों 2 उन्नत होता जा रहा हैं त्यों त्यों आधुनिक मत भी पुराण-वर्णन के निकट आ रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि पुराणोक्त खगोलविद्या त्रिकालदर्शी महर्षियों की तपश्चर्या का ही फल है।

क्रमशः ...



आज महाराणी अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि है। आज भी मालवा क्षेत्र में अहिल्याबाई का नाम पूरे अदब से लिया जाता है। इंदौर शहर को अहिल्या नगरी भी कहा जाता है। अहिल्याबाई होलकर के शासनकाल के दौरान मराठा-मालवा साम्रज्य ने बड़ी-बड़ी विजय प्राप्त की थी। उन्होंने कई सारे हिंदू मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। वे एक बेहिसाब योद्धा थी।

31 मई, 1725 को अहिल्याबाई का जन्म महाराष्ट्र के चेंडी गांव में हुआ था, बचपन से ही उनके मन में दया भाव बहुत अधिक था। उनके पिता का नाम मानको जी शिंदे था। वह धनगर समाज से ताल्लुक रखते थे। वह एक सरपंच थे। अहिल्याबाई किसी राजघराने परिवार से नहीं थीं।

अहिल्याबाई उस जमाने की थी जब लड़कियों के लिए शिक्षा अधिक मायने

नहीं रखती थी, ना ही उस दौरान शिक्षा का बहुत अधिक प्रचलन था। लेकिन अहिल्याबाई के पिता ने उन्हें घर पर ही पढ़ना-लिखना शुरू कर दिया। पढाई के साथ उन्हें शास्त्र ज्ञान भी सिखाया।

अहिल्याबाई होलकर पर जब मालवा के शासन की जिम्मेदारी आई वह तैयार थी लेकिन स्त्री होने के नाते उनकी राह आसान नहीं थी। अतः चारों ओर से उन्हें विरोध की लौ में भी जलना पड़ना लेकिन वह उसमें और अधिक मजबूत बनकर उभरीं। और 11 दिसंबर, 1767 को वे स्वयं इंदौर की शासक बन गईं। राज्य में एक तबका था जो उनके विरोध में था लेकिन होलकर सेना हमेशा उनके समर्थन में रहीं। वहीं रानी भी हर लड़ाई में अपनी सेना के साथ ही खड़ी रहीं। अपनी सेना का नेतृत्व किया, उनका



हौंसला बढ़ाया।

अपने पंसदीदा हाथी पर चढ़कर युद्ध में उतरी, तीर-कमान से अन्य सेनाओं पर हमला किया। अहिल्याबाई की बहादुरी देखकर समूचे देश में उनकी चर्चा होने लगी। उन्होंने

मालवा और प्रजा को रक्षा की। क्षेत्रों को लूटने से बचाया। धीरे-धीरे अहिल्याबाई जिम्मेदारियों का बांटती गईं।

उन्होंने अपने विश्वसनीय सेनानी सूबेदार तुकोजीराव होलकर को सेना प्रमुख बनाया। अहिल्याबाई को बचपन से ही शास्त्र का ज्ञान और चलाना सिखाया गया। लेकिन इसके साथ वह एक अच्छी रणनीतिकार भी थी।

अहिल्याबाई प्रजा कर समस्या के लिए हर दिन एक सार्वजनिक सभा रखती थीं। और जल्द से जल्द प्रजा की समस्या

का निवारण करती थी। वह हमेशा अपने राज्य और लोगों की आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। 30 साल के शासन में अहिल्याबाई ने एक छोटे से गांव का फकीरभूत शहर का विकास किया। आज मालवा क्षेत्र में बनी सड़कें, किले का श्रेय अहिल्याबाई को ही जाता है।

अहिल्याबाई को जीवन में बहुत अधिक दुख नहीं रहा क्योंकि वह उन सभी से उभर पाने में सक्षम रहीं। लेकिन एक बात का मलाल उन्हें हमेशा रहा कि अपनी जमाई की मृत्यु के बाद बेटी सती हो गई थी। रानी अहिल्याबाई का लंबे वक्त तक शासन रहा। और 13 अगस्त सन् 1795 को 70 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। एनी बेसंट लिखती हैं, इंदौर अपनी उस मोहन और दयालु रानी के लिए जितना शोक मनाए कम था। आज भी उनकी सभी अपार सम्मान के साथ याद करते हैं।

सिर के बदले सिर! कौन है ईरान के जनरल रेजाई

आज का इतिहास

- 1784 भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए पिट्स ईंडिया विधेयक ब्रिटिश संसद में पेश हुआ।
- 1814 दासों के व्यापार को समाप्त करने के लिए ब्रिटेन और हॉलैंड के बीच समझौता।
- 1892 अमेरिकी समाचार पत्र एफ्रो-अमेरिकन का बाल्टीमोर से प्रकाशन शुरू हुआ।
- 1898 जार्ज डेवी के नेतृत्व में अमेरिकी सेना ने फिलिपींस की राजधानी मनीला पर कब्जा किया।
- 1902 इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को एक विकेट से हराकर ओवल की प्रसिद्ध जीत दर्ज की।
- 1913 इंग्लैंड के हेरी ब्रेअलैंड, शेफील्ड ने स्टैनलेन स्टील का आविष्कार किया।
- 1951 भारत में निर्मित पहले विमान हिंदुस्तान ट्रेनर 2 ने पहली उड़ान भरी।
- 1956 राष्ट्रीय राजमार्ग लोकसभा में विधेयक पारित हुआ।
- 1977 अंतरिक्ष शटल के पहले ग्लाइड का परीक्षण किया गया।
- 1993 वाशिंगटन में इजरायल एवं फिलिस्तीन के बीच शांति समझौता सम्पन्न।
- 1993 थाईलैंड के नाखोन रचासिमा में होटल ढह जाने से 114 लोग गए।
- 1994 सं.रा. अमेरिका और उत्तरी कोरिया के बीच जेनेवा में परमाणु निरस्त्रीकरण के संबंध में ऐतिहासिक सहमति।
- 1999 लेखिका तसलीमा नसरिन की नई पुस्तक आमार मपेबेला (मेरा बचपन) पर बांग्लादेश सरकार ने प्रतिबंध लगाया, स्टेफ़ी ग्राफ़ ने टैमिस से सन्ध्यास लिया।
- 2000 रोनाल्ड वेनेशिनअन सूरीनाम के नये राष्ट्रपति नियुक्त।
- 2002 इंटरपोल ने नेपाल के 8 माओवादी आतंकवादियों की तलाश के लिए रेड क्वॉरं नोटिस जारी किया।
- 2004 यूनाी सभ्यता की नुमाइश के साथ ओलम्पिक शुरू।
- 2004 ग्रीस के एथेंस में 28 वां ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई।
- 2005 श्रीलंका के विदेश मंत्री लक्ष्मण कादिरगमर की हत्या एवं उसके बाद इमरजेंसी लागू।
- 2008 विश्व की प्रमुख इस्पात कंपनी टाटा स्टील ने वियतनाम में संयुक्त रूप से इस्पात परिसर के निर्माण के लिए वहाँ की दो प्रमुख कंपनियों के साथ समझौता किया।
- 2008 भारत ने मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर (एमबीआरएल) वीपन सिस्टम पिनाक का सफल परीक्षण किया।
- 2008 प्रसिद्ध अर्धशास्त्री व रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती संराजन को राज्यसभा के लिए नामित किया गया।



भी किया था। 1986 में वे ईरान के सुप्रीम डिफेंस काउंसिल के भी सदस्य रहे हैं। 1997 में सैन्य कमान छोड़ने के बाद रिजाई राजनीतिक और देश की नीतियों को गढ़ने में लग गए। वे लगातार देश के राष्ट्रपति चुनाव की रेस में रहे। साल 2009, 2013 और 2021 चुनाव में इब्राहिम रही के बाद करीब 34 लाख वोटों के साथ वे दूसरे स्थान पर रहे। सैन्य मामलों के अलावा रिजाई अर्थशास्त्र और सरकारी नीतियों पर भी मजबूत पकड़ रखते हैं। वे 2021 से 2023 तक ईरान के उपराष्ट्रपति रहे हैं और फिलहाल एक्सपीडिएंसि डिसनमेंट काउंसिल के सदस्य होने के साथ-साथ सुप्रीम काउंसिल फॉर इकोनमिक कोऑर्डिनेशन के सचिव का पद भी संभाल रहे हैं। जानकारों का मानना है कि रजाई जैसे अनुभवी और बेहद सख्त मिजाज जनरल को सुरक्षा परिषद में सर्वोच्च प्रतिनिधि नियुक्त करने का मतलब साफ है। ईरान अब पश्चिमी ताकतों के सामने चुकने के मूड़ में बिल्कुल नहीं। रिजाई ना केवल सैन्य मोर्चे की बारियों को समझते हैं बल्कि आर्थिक पारब्दियों के निपटने और रणनीतिक समझ रखने में महारत हैं।

28 फरवरी 2026 को अमेरिकी-इजराइली हमलों में अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद सत्ता संभालने वाले नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने शुरुआती हमलों में घायल होने के बावजूद अपने भरोसेमंद प्रतिनिधियों के जरिए काम करते हुए सेना और सुरक्षा तंत्र पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। इसी रणनीतिक फेरबदल के तहत उन्होंने ईरान-इराक युद्ध के अनुभवी रेजाई को अपने शीर्ष सैन्य गुट में शामिल किया है, वहीं आर्मड

नीरज कुमार दुबे

राहुल गांधी का प्रयागराज आकर छात्रों से संवाद करना अपने आप में कोई असामान्य राजनीतिक घटना नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष के नेता का युवाओं के बीच जाना, उनकी समस्याएं सुनना और सरकार से सवाल पूछना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन राजनीति में किसी कार्यक्रम का समाचार बन जाना और उसका चुनावी प्रभाव पैदा करना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। यहीं अंतर उत्तर प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में राहुल गांधी के प्रयागराज कार्यक्रम ‘छात्रों की गूंज’ को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है।

कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को पेपर लोक, बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं और युवाओं की समस्याओं के खिलाफ एक बड़े अभियान के रूप में पेश किया है। प्रयागराज का चयन भी प्रतीकात्मक है, क्योंकि यह देश के प्रमुख शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा केंद्रों में गिना जाता है। कांग्रेस का दावा है कि वह छात्रों की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहती है। लेकिन यहां पहला राजनीतिक सवाल खड़ा होता है कि क्या प्रयागराज में छात्रों की एक बड़ी सभा को पूरे उत्तर प्रदेश के युवा मतदाताओं के राजनीतिक रुझान का संकेत मान लिया जाए?

देखा जाये तो राजनीति में भीड़ और वोट के बीच संगठन नाम की एक चीज होती है। किसी नेता के कार्यक्रम में हजारों लोग आ सकते हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो सकते हैं और मीडिया में कई घंटे तक बहस हो सकती है, लेकिन विधानसभा चुनाव 403 सीटों पर लड़ा जाता है। वहां उम्मीदवार चाहिए, स्थानीय नेतृत्व चाहिए, बूथ स्तर का संगठन चाहिए, चुनाव प्रबंधन चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, ऐसा स्थायी मतदाता आधार चाहिए जो मतदान के दिन पार्टी के साथ खड़ा हो। यहीं कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती दिखाई देती है।

हम आपको याद दिला दें कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को केवल दो सीटें मिली थीं और उसका वोट शेयर लगभग 2.33 प्रतिशत रहा था। यह आंकड़ा किसी सामान्य चुनावी उतार-चढ़ाव का नहीं, बल्कि राज्य में कांग्रेस के संगठनात्मक पतन का संकेत था। हां, 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में उल्लेखनीय वापसी की। कांग्रेस ने छह लोकसभा सीटें जीतीं और उसका प्रदर्शन 2022



की तुलना में स्पष्ट रूप से बेहतर हुआ। लेकिन इस सफलता का कारण समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल होना था। दोनों दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा और विपक्षी वोटों का एक बड़ा हिस्सा एकजुट हुआ। इसलिए 2024 के परिणाम को सीधे-सीधे कांग्रेस के स्वतंत्र उत्तर प्रदेश जनाधार का प्रमाण मानना राजनीतिक रूप से जल्दबाजी होगी।

और यही सवाल 2027 के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर कांग्रेस वास्तव में उत्तर प्रदेश में अपने दम पर इतनी मजबूत हो चुकी है, तो फिर उसके अपने ही सांसदों और नेताओं को समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन जल्द तय करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? अभी एक दिन पहले ही तमाम समाचार रिपोर्टें में कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के सांसदों द्वारा 2027 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को जल्द अंतिम रूप देने की मांग सामने आई है। साथ ही, प्रदेश कांग्रेस के भीतर गठबंधन को लेकर मतभेदों की खबरें भी आती रही हैं। इसलिए राहुल गांधी से एक सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि अगर कांग्रेस का अपना जनाधार इतना मजबूत है, तो 2027 में उसे समाजवादी पार्टी के सहारे की जरूरत क्यों है?

वैसे यह सवाल गठबंधन के खिलाफ नहीं है। गठबंधन लोकतांत्रिक राजनीति का सामान्य हिस्सा है। लेकिन तब 2024 की सफलता को कांग्रेस की अकेले की ताकत बताना भी उचित नहीं होगा। यदि सफलता गठबंधन की संयुक्त ताकत से आई है, तो उसका श्रेय भी ईमानदारी से साझा करना होगा। यही कारण है कि प्रयागराज का ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन इसे 2027 के चुनाव की दिशा बदल देने वाला कार्यक्रम मानने के लिए अभी बहुत कुछ साबित होना बाकी है।

कांग्रेस को यह बताना होगा कि प्रयागराज की

मोहन भागवत की नजरों में जेन-जी आंदोलन का दृष्टिकोण

ललित गर्ग

जंतर-मंतर से उठी हाल की युवा आवाजों ने भारतीय लोकतंत्र के सामने कई नए प्रश्न खड़े किए हैं। आंदोलन को लेकर समाज में दो मत हो सकते हैं, आंदोलन की शैली, नेतृत्व और उसके राजनीतिक इस्तेमाल पर भी बहस हो सकती है, लेकिन एक बुनियादी सत्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को अपनी बात कहने, असहमति व्यक्त करने और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने का अधिकार है। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का युवाओं और विशेषकर जेन-जी को लेकर दिया गया दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है।

उन्होंने साफ कहा कि नई पीढ़ी सवाल करती है, तर्कसंगत उत्तर चाहती है, उसे केवल आदेश देकर नहीं समझाया जा सकता। उनके अनुसार आज जरूरत ‘डिफेंशन’ की नहीं, ‘डिस्कशन’ की और आदेश की नहीं, सहमति की है। भागवत ने हाल में इससे भी आगे बढ़कर कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन संवाद का एक वैध माध्यम है और जेन-जी के आंदोलन में उठाई गई शिकायतें जायज हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विरोध करने वालों को राष्ट्रविरोधी कह देना उचित नहीं है। उनका मानना है कि आंदोलन का उद्देश्य समाज में विभाजन पैदा करना नहीं, बल्कि सहमति और समाधान की दिशा में आगे बढ़ना होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत और छात्रों की नाराजगी के बीच संबंध की ओर भी उन्होंने संकेत किया।

भागवत के इस दृष्टिकोण की सराहना इसलिए भी की जानी चाहिए कि यह केवल किसी एक आंदोलन या किसी एक सरकार का प्रश्न नहीं है। यह भारतीय लोकतंत्र की उस मूल आत्मा को स्पर्श करता है, जिसमें सत्ता जनता से शक्ति प्राप्त करती है और जनता की आवाज सुनना उसकी संवैधानिक तथा नैतिक जिम्मेदारी है। विरोध को हमेशा विद्रोह मान लेना लोकतंत्र की समझ को संकुचित करना है। असहमति को राष्ट्रविरोध समझना उससे भी बड़ी भूल है। राष्ट्र सरकार से बड़ा है और लोकतंत्र सत्ता से बड़ा। जो नागरिक देश के भविष्य को लेकर सवाल करता है, वह जरूरी नहीं कि देश का विरोध कर रहा हो, कई बार वह देश को बेहतर बनाने की बेचैनी व्यक्त कर रहा होता है।

आजादी की वर्षगांठ के अवसर पर जब हम स्वतंत्र भारत की उपलब्धियों का उत्सव मनाते हैं, तब हमें यह भी पूछना चाहिए कि हमारी आजादी का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या आजादी केवल तिरंगा पहनाने, राष्ट्रगान गाने और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने तक सीमित है? या इसका अर्थ यह भी है कि देश का युवा अपने भविष्य को लेकर सवाल कर सके, व्यवस्था की कमियों की ओर ध्यान आकर्षित कर सके और अपनी बात बिना भय के रख सके? यदि हम सचमुच विकसित भारत, समृद्ध भारत और शक्तिशाली भारत का सपना देखते हैं तो हमें भारत के युवाओं के सपनों को सुनना ही होगा।

भारत के महान चिंतकों ने युवाशक्ति को राष्ट्रनिर्माण का आधार माना है। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को जागने, अपनी शक्ति



पहचानने और लक्ष्य की ओर बढ़ने का आह्वान किया था। उनके चिंतन का मूल संदेश यही था कि युवा केवल राष्ट्र का भविष्य नहीं, वर्तमान की सक्रिय शक्ति भी हैं। महात्मा गांधी का विश्वास था कि परिवर्तन केवल सत्ता के गलियारों से नहीं आता, वह जागरूक नागरिकों की चेतना से आता है।

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने बार-बार युवाओं के सपनों को भारत के भविष्य से जोड़ा। उनके लिए सपना वह नहीं था जो सोते समय दिखाई देता है, बल्कि वह था जो व्यक्ति को सोने नहीं देता। आज के युवाओं की बेचैनी को इसी दृष्टि से समझने की आवश्यकता है। नई पीढ़ी और पिछली पीढ़ी के बीच अंतर स्वाभाविक है। पहले परिवार, विद्यालय और समाज में ‘क्यों’ पूछने की गुंजाइश कम थी, बड़े जो कहते थे, उसे मान लेना संस्कार समझा जाता था। आज का युवा प्रश्न करता है-क्यों, कैसे और किसलिए? वह केवल परंपरा के नाम पर किसी बात को स्वीकार नहीं करता। वह प्रमाण चाहता है, तर्क चाहता है और परिणाम देखना चाहता है। यह बदलाव चुनौती भी है और अवसर भी। यदि हम इस प्रश्नाकुलता को दबाएंगे तो कुंठा पैदा

होगी, यदि इसे सही दिशा देंगे तो यही प्रश्न नवाचार, अनुसंधान और राष्ट्रनिर्माण की शक्ति बनेंगे।

विचारों के टकराव से घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय संस्कृति स्वयं ‘वादे वादे जायते तत्त्वबोधः’ की संवाद परंपरा से विकसित हुई है। उपनिषदों में प्रश्न हैं, उत्तर हैं, पुनः प्रश्न हैं। भगवान महावीर की अनेकांत दृष्टि हमें सिखाती है कि सत्य को एकांगी दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। एक ही विषय के अनेक पक्ष हो सकते हैं। इसलिए बहस लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी बौद्धिक ताकत है। समस्या बहस में नहीं, बहस के हिंसक हो जाने में है, समस्या असहमति में नहीं, असहमति के नाम पर अराजकता में नहीं, इसलिए भागवत की बात का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है-विरोध संविधान की मर्यादा में हो, शांतिपूर्ण हो और उसका लक्ष्य व्यक्ति को अपमानित करना नहीं, व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन लाना हो।

आंदोलन लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन लोकतांत्रिक अनुशासन के साथ। सरकार की आलोचना लोकतंत्र है, हिंसा लोकतंत्र नहीं। प्रश्न करना स्वतंत्रता है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना स्वतंत्रता नहीं। इसलिए सरकार और आंदोलनकारी-दोनों की जिम्मेदारियां हैं। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी अधिक बड़ी है, क्योंकि उसके पास सत्ता, प्रशासन और संस्थागत शक्ति होती है। किसी छात्र की

आवाज को लाठी से दबाया जा सकता है, लेकिन उसकी आशंका को लाठी से समाप्त नहीं किया जा सकता। किसी आंदोलनकारी को राष्ट्रविरोधी कह देने से उसका प्रश्न समाप्त नहीं हो जाता। यदि उसकी मांग गलत है तो तथ्य और तर्क से उसे गलत सिद्ध किया जाए। यदि मांग सही है तो उसे स्वीकार करने में संकोच क्यों? लोकतंत्र में सरकार का सबसे प्रभावी हथियार पुलिस नहीं, संवाद है।

यहां मोहन भागवत की भूमिका एक मार्गदर्शक की तरह दिखाई देती है। उन्होंने अनेक अवसरों पर केवल प्रशंसा करने के बजाय व्यापक सामाजिक हित के प्रश्न उठाए हैं। जब सत्ता या व्यवस्था किसी दिशा में आवश्यकता से अधिक आगे बढ़ती दिखाई देती है, तब एक जिम्मेदार मार्गदर्शक का दायित्व होता है कि वह उसे आत्ममथन की ओर ले जाए। भागवत की यह भूमिका हमें महाभारत के भीष्म पितामह की याद दिलाती है-ऐसे व्यक्ति की, जो सत्ता के केंद्र में रहते हुए भी समय-समय पर धर्म, मर्यादा और व्यापक हित की याद दिलाता है। यह तुलना व्यक्त-पूजा के लिए नहीं, बल्कि मार्गदर्शक की भूमिका की व्याख्या के लिए है। सरकारें जब जनता की आवाज समय पर सुनती हैं तो आंदोलन समस्या बनने से पहले समाधान बन सकता है। लेकिन जब शिकायतें महीनों और वर्षों तक फाइलों में पड़ी रहती हैं, जब संवाद के रास्ते बंद होते जाते हैं और जब नागरिक को लगता है कि उसकी सुनवाई नहीं होगी, तब असंतोष सड़क पर आता है। फिर वही आंदोलन राजनीतिक दलों, अवसरवादी तत्वों और निहित स्वार्थों के लिए मैदान बन जाता

है। परिणामतः मूल मुद्दा पीछे छूट जाता है और आंदोलन का चरित्र बदलने लगता है। यही वह स्थिति है जिससे लोकतंत्र को बचना है।

नीट और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े विवादों ने भी यही संदेश दिया है कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों में सरकार और संस्थाओं को असाधारण संवेदनशीलता दिखानी होगी। परीक्षा केवल एक प्रश्नपत्र नहीं होती, वह लाखों परिवारों के वर्षों के परिश्रम, सपनों और आर्थिक-सामाजिक आकांक्षाओं से जुड़ी होती है।

यदि किसी विद्यार्थी को लगता है कि उसकी मेहनत निष्पक्ष व्यवस्था में नहीं आंकी गई, तो उसका आक्रोश स्वाभाविक है। हाल के छात्र आंदोलनों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है। इस संदर्भ में पुलिस की भूमिका भी पुनर्परिभाषित करने की जरूरत है। हर प्रदर्शनकारी अपराधी नहीं होता और हर नारा राष्ट्रविरोधी नहीं होता। पुलिस को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का प्रशिक्षण भी मिलना चाहिए। राष्ट्रविरोधी गतिविधि और जायज नागरिक असहमति के बीच अंतर करना लोकतांत्रिक पुलिस व्यवस्था की पहली कसौटी है। इसलिए मोहन भागवत की बात को केवल जेन-जी आंदोलन के संदर्भ में देखने की बजाय उसे शासक की लोकतांत्रिक यात्रा के व्यापक संदेश के रूप में देखा जाना चाहिए। सरकारें आएंगी-जाएंगी, राजनीतिक दल बदलेंगे, आंदोलनों के स्वरूप बदलेंगे, लेकिन लोकतंत्र की बुनियादी आवश्यकता नहीं बदलेगी, जनता को सुनना होगा।

प्रधानमंत्री मोदी का कद बढ़ा, भाजपा पीछे, कांग्रेस आगे!

हरीश गुप्ता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंट्रग्रापम पर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया है जिसकी बराबरी दुनिया का कोई भी राजनेता नहीं कर सकता। 10.5 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स के साथ, वे राहुल गांधी को बौना साबित करते हैं, जिनके लगभग 1.3 करोड़ फॉलोअर्स हैं।

लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर भाजपा के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल की तुलना में कहीं अधिक फॉलोअर्स हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो, राहुल गांधी को मोदी पछाड़ रहे हैं, फिर भी भाजपा से कांग्रेस आगे है। यह विरोधाभास संयोगवश नहीं है। यह दर्शाता है कि पिछले एक दशक में भारतीय राजनीति में किस प्रकार परिवर्तन आया है।

भाजपा धीरे-धीरे महज एक राजनीतिक दल होने से आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी के एक शक्तिशाली राजनीतिक ब्रांड का माध्यम बन गई है। उनके भाषण, यात्राएं, कूटनीति, ‘मन की बात’ कार्यक्रम, योग सत्र और चुनावी रैलियां पार्टी की हलचल का केंद्र बन गई हैं। लाखों लोगों को भाजपा को अलग से देखने की कोई खास जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि उनके मन में मोदी ही भाजपा हैं।

दूसरी ओर, कांग्रेस का कामकाज अलग है। राहुल गांधी बेशक पार्टी के प्रमुख प्रचारक बन गए हैं, लेकिन कांग्रेस का इंस्टाग्राम अकाउंट पूरे विपक्षी तंत्र का डिजिटल मुख्यालय बन गया है। भाजपा विरोधी कई मतदाताओं के लिए, राहुल के निजी पेज के बजाय कांग्रेस का अकाउंट ही उनकी पहली पसंद बन गया है।

दूसरे, आधुनिक चुनाव तेजी से राष्ट्रपति पद के चुनावों की तरह होते जा रहे हैं। अगली मुकाबला अब सिर्फ भाजपा और कांग्रेस या मोदी और राहुल

गांधी के बीच नहीं है। यह राजनीतिक व्यक्तित्व की शक्ति और राजनीतिक संगठन की ताकत के बीच का मुकाबला है।

ऐसा लगता है कि भाजपा ने अचानक प्रेम, स्नेह और सबसे बढ़कर सहयोगियों के महत्व को समझ लिया है। महीनों तक राजनीतिक आत्मविश्वास प्रदर्शित करने के बाद, पार्टी नेतृत्व ने चुनचाप अधिक सुलहपूर्ण रख अपना लिया है और स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वह सुनने के लिए तैयार है और शायद थोड़ा झुकने के लिए भी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखवीर सिंह बादल से मुलाकात को इसी तरह का एक संकेत माना जा रहा है। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा के परिवार के प्रति भाजपा के सद्भावपूर्ण रवैये और उनके बेटे को विधान परिषद में स्थान दिए जाने पर भी काफी चर्चा हो रही है। और फिर नीतीश कुमार।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री 20 जुलाई से संसद सत्र के लिए दिल्ली में थे, फिर भी भाजपा को अचानक उन्हें बैठक के लिए आमंत्रित करने की जरूरत महसूस हुई। कुछ अन्य छोटे लेकिन महत्वपूर्ण संकेत भी हैं। दो घटनाक्रमों ने इसमें भूमिका निभाई है- हाल ही में हुए उपचुनावों में भाजपा की अप्रत्याशित हार और अभिजीत दीपके के नेतृत्व वाली काँजपा की आश्चर्यजनक सफलता,

जिसने यह प्रदर्शित किया कि स्थापित दलों के बाहर का राजनीतिक क्षेत्र भी अचानक गति पकड़ सकता है। ऐसा लगता है कि भाजपा को यह एहसास हो गया है कि प्रभुत्व का मतलब यह नहीं है कि वह सहयोगियों, मतदाताओं या उभरती राजनीतिक ताकतों को हल्के में ले सकती है। इसलिए, फिलहाल भाजपा शांति मिशन पर है। और ऐसा लगता है कि मेल-मिलाप का सिलसिला शुरू हो गया है।

ऐसे तो फिर हाथ से फिसल जाएगी सत्ता की कुर्सी!

डॉ. श्रीगोपाल नारसन

हाल ही में गठित उत्तराखंड कांग्रेस की भारी भरकम कार्यकारिणी में हरीश रावत का नाम नदारद है,कुछ ऐसे चर्चित और प्रभावी नाम भी कार्यकारिणी में नही है ,जिनके नाम से ही कांग्रेस जानी जाती है।साथ ही जो मुसलमान कांग्रेस को आंख बंद करके वोट देता आया है,उनकी संख्या कार्यकारिणी में मात्र 8 है।वह भी तब जब कार्यकारिणी के प्रदेश सचिवों की संख्या ही 107 तक पहुंच गई है।एक तरफ उत्तराखंड में कार्यकारिणी गठन का ऐलान हो रहा था,वही दूसरी तरफ दिल्ली से खबर आ रही थी कि हरीश रावत जिंदगी की जंग लड़ रहे है।हल्द्वानी में हुई कांग्रेस अध्यक्ष मस्जिदार्जुन खड़गे की जनसभा में कुछ कार्यकर्ताओं ने हरीश रावत जिंदाबाद के नारे उनकी गैर मौजूदगी में लगा दिए तो कांग्रेस प्रभारी शैलजा नाराज हो गई,जबकि होना यह चाहिए था कि जनसभा में हरीश रावत को भी आमंत्रित कर उनका भाषण कराया जाता।नहीं का कांग्रेस अपने को दूर करके क्या हासिल करना चाहती है।कांग्रेस में योग्य कार्यकर्ताओ की कमी नही है,परन्तु गुटबाजी के चक्कर मे उन्हें आगे ही नही लाया जाता।पार्टी के प्रभारी जो नेता बनते है,उनकी भी परफॉमेंस का आंकलन करना चाहिए कि उन्हीने अपने रण्यो में पार्टी को कितनी सीटे दिलवाई, ऐसे न हो कि अपने रण्यो में हारकर दूसरे राज्य का प्रभारी बन सिर्फ अपने स्वस्त करता हुआ ही प्रभारी घूमता रहे।कम से कम भाजपा में ऐसा नही होता,वहां निष्ठावान कार्यकर्ताओ को खोज खोजकर दायित्व दिया जाता है।जबकि कांग्रेस में चापलूची, चमचांगिरी और जी हुजुरी पहले नंबर पर है



तभी कुछ मिल सकता है।।आज पार्टी में ऐसे ऐसे पदाधिकारी बन बैठे है ,जो पार्टी के प्रति शायद ही वफादार रहे हो।आगामी 2027 के मद्देनजर होना यह चाहिए था कि कांग्रेस सबको साथ लेकर चलती।लेकिन हाल के घटनाक्रम तो आपसी फूट की तरफ इशारा कर रहे है।कांग्रेस के लिए यह स्वर्णिम अवसर है जब भाजपा के मौजूदा 32 विधायकों की रिपोर्ट खराब आई है,यदि उन्ही सीटों को कांग्रेस टारगेट बना ले तो उसकी नैया पार हो सकती है।लेकिन न तो हरीश रावत के बिना और न ही पार्टी के उन निष्ठावानों के बिना ,जो कांग्रेस को अपने खून से सींचते है।

हरीश रावत एक मात्र ऐसे नेता है जो अपने कार्यकर्ताओं के बीच सदैव सक्रिय रहते है।उनके बिना कांग्रेस आज भी बेमायब है।पिछले दिनों की कांग्रेस प्रभारी शैलजा से अप्रत्यक्ष नाराजगी के चलते हरीश रावत ने अर्जित अवकाश की राजनीति शुरू की थी।जिसे लेकर कांग्रेस के आला अधिकारी से लेकर कांग्रेस समर्थक भी असमंजस में रहे।अपनी बढ़ती उम्र में भी बेहद सक्रिय कांग्रेस के शीर्ष नेता हरीश रावत के पास वर्तमान में कोई दायित्व नही है,फिर भी वे राज्य के सर्वाधिक सक्रिय नेता कहे जा सकते है।ऐसे में उनकी अनदेखी करके कांग्रेस कोई भी चुनाव फिलहाल नही लड़ सकती

आजाद होते ही बलूचिस्तान बोला, धन्यवाद हिंदुस्तान

नीरज कुमार दुबे

सोशल मीडिया इस समय ऐसे वीडियोज से भरा पड़ा है, जिनमें बलूचिस्तान के लोग अपनी आजादी का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। 11 अगस्त को बलूचिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाए गए कार्यक्रमों के बीच बलूच अलगाववादी नेतृत्व ने अब अपने अभियान को एक नया राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश भी की है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की अपील की है। साथ ही भारत की ओर से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर उठाई गई आवाज की खुलकर सराहना की है।

मीर यार बलूच ने एक्स पर जारी अपने संदेश में भारतीय मीडिया का विशेष रूप से आभार जताया। उनका कहना था कि भारतीय मीडिया ने 11 अगस्त को बलूचिस्तान में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के उस बयान का भी स्वागत किया, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर और उसके नियंत्रण वाले अन्य क्षेत्रों में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की जरूरत पर जोर दिया गया था। हालांकि जायसवाल ने बलूचिस्तान का सीधे तौर पर उल्लेख नहीं किया था, लेकिन बलूच नेतृत्व ने भारत के इस व्यापक मानवाधिकार रुख को अपने पक्ष में महत्वपूर्ण संकेत के तौर पर पेश किया है।

यही वह बिंदु है जो इस पूरे घटनाक्रम को केवल बलूचिस्तान के भीतर रह कर अलगाववादी आंदोलन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। बलूच नेतृत्व अब अपने आंदोलन को अंतरराष्ट्रीय वैधता दिलाने की दिशा में ले जाने का दावा कर रहा है। उसके संदेश में संयुक्त राष्ट्र, आसियान, अफ्रीकी संघ, इस्लामिक सहयोग संगठन और यूरोपीय देशों से बलूचिस्तान के पक्ष में आवाज उठाने की



अपील की गई है। संगठन का दावा है कि अब लड़ाई केवल स्वतंत्रता दिवस मनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता की कानूनी, राजनीतिक, कूटनीतिक और नैतिक मान्यता हासिल करने की है। बलूच नेतृत्व ने 11 अगस्त की तारीख को भी ऐतिहासिक आधार देने की कोशिश की है। उसका दावा है कि ब्रिटिश शासन के अंत और भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन से ठीक पहले 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। इसी ऐतिहासिक दावे को आधार बनाकर मौजूदा अभियान को अंतरराष्ट्रीय मान्यता की लड़ाई बताया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान और अंतरराष्ट्रीय समुदाय बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के इस दावे को मान्यता नहीं देते और बलूचिस्तान को पाकिस्तान का एक प्रांत माना जाता है।

वैसे इस अभियान का अगला चरण और भी महत्वपूर्ण है। बलूच समूह ने दावा किया है कि भविष्य के स्वतंत्र राष्ट्र के लिए विदेश नीति, रक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति और कूटनीति से जुड़े ढांचे तैयार किए जा रहे हैं। उसने पासपोर्ट, अपनी मुद्रा, मीडिया संस्थानों, व्यापारिक संस्थाओं और विदेशों में राजनयिक मिशनों की तैयारी का भी दावा किया है। साथ ही अलग-अलग बलूच राजनीतिक धाराओं को एकजुट करने की कोशिश की बात कही गई है।

बलूच नेतृत्व ने पाकिस्तान पर दमन का भी गंभीर आरोप लगाया है। उसके मुताबिक 50 हजार से अधिक बलूच लोग अब भी यातना केंद्रों में अमानवीय

परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। बलूचों ने जबरन गुमशुदगी, हिरासत और लश्कित हत्याओं जैसे मुद्दों को भी उठाया है। बलूचों के समूह ने यह भी आरोप लगाया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह रोकने के लिए मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद की गईं, सैन्य छावनियों और पुलिस प्रतिष्ठानों के आसपास खाइयां खोदी गईं तथा ड्रोन, हेलीकॉप्टर और सैन्य विमानों से निगरानी की गई। राजनीतिक रूप से देखें तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए बेहद संवेदनशील भूभाग है। क्षेत्रफल के लिहाज से यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध माना जाता है। बलूच नेतृत्व का दावा है कि स्वतंत्र बलूचिस्तान अपने संसाधनों के जरिये स्वास्थ्य, शिक्षा और मानवीय सहायता के क्षेत्र में योगदान दे सकता है। यही संसाधन, भौगोलिक स्थिति और लंबे समय से जारी विद्रोह इसे पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के साथ-साथ क्षेत्रीय भू-राजनीति का भी अहम मुद्दा बनाते हैं।

भारत के लिए इसका रणनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि बलूचिस्तान का मुद्दा पाकिस्तान के उस नैरेटिव को चुनौती देता है, जिसमें वह जम्मू-कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लगातार उठाता रहा है। बलूच नेतृत्व का भारत की मीडिया और विदेश मंत्रालय के बयानों को अपने पक्ष में उद्धृत करना पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाने की कोशिश है। हालांकि भारत की ओर से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने की कोई घोषणा इन स्रोतों में नहीं है। बहरहाल, बलूचिस्तान में चल रहा संघर्ष अब केवल बंदूक और सुरक्षा बलों के बीच की लड़ाई नहीं रह गया है। यह इतिहास, मानवाधिकार, संसाधनों, अंतरराष्ट्रीय मान्यता और सूचना युद्ध, इन सभी मोर्चों पर लड़ जा रही लड़ाई बनता जा रहा है। और जिस तरह बलूच नेतृत्व भारत का सार्वजनिक रूप से आभार जता रहा है, उससे साफ है कि वह इस संघर्ष को पाकिस्तान की सीमाओं से बाहर निकालकर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के मैदान में ले जाना चाहता है।

3 चुनाव, तीन चेहरे और 3 अलग पार्टियों ने मारा मैदान

अमन तिवारी

देश की राजधानी दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक जिला है-शामली। यूं तो शामली के पहले एक तहसील और फिर एक जिले के तौर पर अस्तित्व में आने की अपनी अलग कहानी है, लेकिन जिले के गठन के साथ ही शामली विधानसभा सीट का अलग होना और इस पर बीते चुनाव अपने आप में जिले के जातीय समीकरणों की दिलचस्प कहानी कहते हैं। आइये जानते हैं शामली विधानसभा सीट के इतिहास और इस पर हुए अब तक के चुनावों के बारे में... उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से एक जिला है शामली। इस जिले के अंतर्गत तीन तहसील, पांच ब्लॉक और 322 गांव आते हैं। इस जिले की शामली विधानसभा सीट 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। शामली विधानसभा सीट पर पहली बार चुनाव 2012 में हुए थे। राजनीतिक रूप से यह क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट-मुस्लिम समीकरणों, गन्ना किसानों के मुद्दों और एंटी-इस्कबेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर के अन्तुे इतिहास के लिए जाना जाता है।

1. 2012 के विधानसभा चुनाव 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार पंकज कुमार मलिक ने जीत दर्ज की थी। जाट समुदाय से आने वाले पंकज को कुल 53,947 वोट मिले थे। कांग्रेस ने यह चुनाव राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के साथ मिलकर लड़ा था। वहीं, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह दूसरे स्थान पर रहे थे, जिन्हें कुल 50,206 वोट हासिल हुए थे। यानी पंकज मलिक ने यह चुनाव महज

3,741 वोटों के करीबी अंतर से जीता था। इस सीट पर तब बसपा प्रत्याशी को 45,597 वोट मिले थे, जबकि भाजपा उम्मीदवार महज 9,105 वोट ही हासिल कर पाए।

2. 2017 के विधानसभा चुनाव एक बार फिर इस सीट पर जाट समुदाय के ही उम्मीदवार को जीत मिली। भाजपा के तेजेंद्र निर्वाल को 2017 में इस सीट पर 70,085 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के पंकज कुमार मलिक बसपा 40,365 वोट ही हासिल कर सके। यानी उनकी करीब 30 हजार वोटों से हार हुई। पंकज की हार की एक बड़ी वजह कांग्रेस और रालोद का गठबंधन टूटना रहा, जिसके चलते रालोद ने अपना अलग उम्मीदवार उतारा। चुनाव में रालोद के बिजेंद्र सिंह को 33,551 वोट मिले, जो कि कांग्रेस की हार का बड़ा कारण बनी। इसके अलावा निर्दलीय मनीष कुमार को 31,824 वोट और बसपा के मोहम्मद इस्लाम को 17,114 वोट मिले।

3. 2022 के विधानसभा चुनाव 2022 के चुनाव से ठीक पहले हुए तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन ने यहां के राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल दिए। जाट और मुस्लिम मतदाताओं के बड़े धड़े एकजुट हो गए। नतीजतन राष्ट्रीय लोक दल के प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी ने 48.86व वोट हासिल किए। रालोद ने यह चुनाव सपा के साथ गठबंधन में लड़ा था। चौधरी ने इस चुनाव में भाजपा के तेजेंद्र निर्वाल को कड़े मुकाबले में मात दी और विधायक बने। जहां प्रसन्न को 1,03,070 वोट मिले। वहीं, भाजपा को 95,963 वोट हासिल हुए।

नकारात्मक लोगों को कैसे पहचानें?



जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं वो जाने-अनजाने में आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। कहीं न कहीं हम उनकी तरह बात करने, उनकी तरह बनने और वैसे ही करने की कोशिश अनजाने में करने लगते हैं, ये मानवीय पकृति है जिसे हर कोई करता है और इसे बदलना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि संगत का असर दिमाग पर पड़ता है और दिमाग एक जटिल अंग है जिसे समझ पाना असंभव है। कई बार हमें पता ही नहीं चलता है कि जो लोग हमारे साथ या आसपास हैं वो कितने बेकार और नकारात्मक सोच वाले हैं। ऐसे लोग विपैले सांप की तरह होते हैं जो कभी न कभी आपको भी नुकसान पहुंचाते ही हैं। इसलिए, बेहतर होगा कि ऐसे लोगों को पहचानें और उनसे दूरी बना लें। ऐसे लोग अपनी बातों या अपने कामों से आए दिन किसी न किसी का दिल दुखाते रहते हैं। वे हमेशा कोशिश करेंगे कि वे आपको बहुत भला चाहते हैं लेकिन आपको निराश करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं। ऐसे लोगों को स्मार्टली हैंडल करना सीखें और उनसे भावनात्मक दूरी बना लें। वरना वे आपमें भी ऐसी आदत पनपा सकते हैं। ऐसे लोग हमेशा परेशान रहते हैं। वो जीवन में कभी खुश नहीं रहते हैं। चाहें परिस्थितियां कितनी भी अच्छी क्यों न हों, उन्हें हमेशा शिकायत और समस्या ही रहती है। समय रहते ऐसे लोगों से दूर हो जाएं। जो लोग आपको किसी काम को करने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं बल्कि हमेशा हतोत्साहित करते रहते हैं वे लोग टॉक्सिक होते हैं। ऐसे लोग जीवन में नकारात्मकता लेकर आते हैं। जितना संभव हो, ऐसे लोगों से दूर रहें। जहरीले स्वभाव वाले लोगों से आप जब भी बात करें, तो वे दूसरों के बारे में हमेशा खराब ही बोलेंगे। इससे आपके नजरिए पर भी असर पड़ता है। इसलिए, अच्छा होगा कि ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें।

डीवीडी देखकर व्यायाम न करें...



एक नए शोध में पता चला है कि फिटनेस डीवीडी देखते हुए घर में व्यायाम करने का विचार अच्छा लग सकता है, लेकिन इसका काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऑरिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में हुए एक शोध के परिणामों से पता चला है कि इस तरह के वीडियो से व्यक्ति की सोच नकारात्मक दिशा की ओर मुड़ सकती है और उनके प्रेरणा स्तर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। फिटनेस के लिए मिलने वाली डीवीडी के अध्ययन से यह भी सामने आया है कि इस तरह की डीवीडी में इस्तेमाल होने वाली निराशाजनक भाषा से व्यायाम करने वालों पर पड़ने वाले प्रभाव का स्तर कम हो सकता है। इसके साथ ही ऐसा वीडियो देखने वाले व्यक्ति की आशा और क्षमता पर पड़ने वाला नकारात्मक प्रभाव मनोवैज्ञानिक क्षति का कारण बन सकता है। इस शोध के लिए शोधकर्ताओं ने व्यायाम का प्रशिक्षण देने वाले 10 लोकप्रिय डीवीडी की समीक्षा की। इस तरह के डीवीडी में इस्तेमाल होने वाली भाषा और वीडियो का मूल्यांकन किया गया। इस शोध का लक्ष्य इस तरह के डीवीडी में दिए जाने वाले संदेशों और वीडियो को बेहतर तरीके से समझना और उपयोगतकर्ताओं पर इनके प्रभाव का आकलन करना था। इन फिटनेस डीवीडी का 25 करोड़ डॉलर का उद्योग है, लेकिन इनकी सुरक्षा से संबंधित कोई भी वैज्ञानिक सबूत नहीं है। इस शोध के परिणामों के बाद सभी उपभोक्ताओं से आग्रह किया गया कि वे इस तरह के डीवीडी को खरीदते समय या इनका इस्तेमाल करते समय इससे पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के प्रति जागरूक रहें।

सैनिक स्कूलों में लड़कियों को भी मिल सकता है दाखिला



सैनिक स्कूलों में अब लड़कियों के दाखिले की भी अनुमति दी जा सकती है। करीब 55 साल पहले जब एक सैनिक स्कूल खुला था तो वह सिर्फ पुरुष प्रधान ही था यानी सिर्फ छात्रों का ही दाखिला होता था। मामले के जानकार एक अधिकारी ने बताया कि नागरिक उद्ययन मंत्री अशोक गजापति राजू ने एक पत्र लिखा था जिसके आधार पर रक्षा मंत्रालय ने इन स्कूलों में लड़कियों को भी दाखिला देने की संभावना तलाशनी शुरू कर दी है। रक्षा मंत्रालय अभी देश भर में 22 सैनिक स्कूल चलाता है। अधिकारी ने बताया कि राजू ने रक्षा मंत्री मनोहर पारिज़्कर को एक पत्र लिखकर आग्रह किया जिस पर पारिंकर ने इस मामले पर गौर करने का वादा किया। देश भर में नैशनल डिफेंस अकेडमी और आर्मी में महिलाओं के दाखिले को लेकर विभिन्न स्तरों पर बहस चल रही थी। सैनिक स्कूल में छात्राओं के प्रवेश को इस दिशा में पहला कदम माना जाएगा।

रक्षा मंत्री को लिखे पत्र में राजू ने उल्लेख किया, 'आज के आधुनिक समय में रक्षा सेवाएं अस्वाभाव नहीं रह गई हैं जहां महिलाएं अपनी भूमिका न निभा सकें। इस संदर्भ में मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि कई पैरंट्स सैनिक स्कूल, कोरूकोडा (विजयनगरम) के माध्यम से देश की सेवा में अपनी लड़कियों को भेजना चाहते हैं।'

विविध

“ अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ऐसा

कर पाने में जो इंसान सक्षम होता है, उसे लगभग आधी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। जीवन में अनुशासन लाकर भावनाओं को एक सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है। आजकल मनोवैज्ञानिक इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा महत्व देने लगे हैं, क्योंकि इसके बिना कोई भी इंसान अपने अर्जित ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं कर सकता।

“

“

आज की जटिल जीवन स्थितियों में खुशी और कामयाबी हासिल करने के लिए व्यक्ति का केवल मेहनती और बुद्धिमान होना ही काफी नहीं, बल्कि इसके लिए भावनात्मक परिपक्वता भी बहुत जरूरी है। आपने यह अनुभव किया होगा कि एक ही जैसी स्थितियों में लोग अलग-अलग ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं।कुछ लोग छोटी-छोटी परेशानियों से हताश हो जाते हैं तो कुछ बेहद मुश्किल हालात में भी घबराने के बजाए शांतपूर्ण ढंग से अपनी समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसमें से दूसरी तरह के लोग भावनात्मक रूप से बुद्धिमान माने जाते हैं और वे जीवन के हर मोर्चे पर कामयाब होते हैं। आजकल मनोवैज्ञानिक भावनात्मक विवेक को बहुत ज्यादा महत्व देने लगे हैं, क्योंकि इसके बिना कोई भी इंसान अपने अर्जित ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं कर सकता। भावनात्मक विवेक के सिद्धांत के प्रतिपादकों का ऐसा मानना है कि पारंपरिक रूप से जिसे हम आइक्यू कहते हैं, उसका क्षेत्र बहुत सीमित है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस का दायरा बहुत विस्तृत है।

क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस

इमोशनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत समस्त मानवीय व्यवहार समाहित हैं। जीवन में सफल होने के लिए केवल मेहनत करके तकनीकी कौशल सीखना और जानकारीयां हासिल करना ही काफी नहीं, बल्कि इंसान को अपनी भावनाओं के बीच संतुलन स्थापित करना भी आना चाहिए। बौद्धिक रूप से कोई भी इंसान चाहे कितना ही सक्षम क्यों न हो लेकिन भावनात्मक परिपक्वता के अभाव में वह असफल हो सकता है।

अंतर्मन के आईने में

अपने व्यक्तित्व को अच्छी तरह समझना भी भावनात्मक विवेक का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि आप किन बातों से खुश होते हैं, कौन सी बातें आपको नापसंद हैं, अगर कभी आपका मूड खराब है तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि किस वजह



इमोशनल इंटेलिजेंस भी जरूरी...

से आपका मूड खराब है। किन बातों को लेकर आप चिंतित और परेशान होते हैं, आपके मन में किन बातों को लेकर असुरक्षा है, यह आपको स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए। जब कभी आप शांतिपूर्वक अकेले बैठे हों तो तटस्थ हो कर दूसरों की नजर से आत्मविश्लेषण करें। जब आप ईमानदारी के साथ अपने व्यक्तित्व का मूल्यांकन करेंगे, तभी आप अपनी भावनाओं को अच्छी तरह समझने में सक्षम होंगे। इससे अपने मनोभावों को नियंत्रित और संतुलित करना आपके लिए सहज होगा।

भावनात्मक अनुशासन

अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ऐसा कर पाने में जो इंसान सक्षम होता है, उसे लगभग आधी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। जीवन में अनुशासन लाकर भावनाओं को एक सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आप अच्छी प्रेरणादायक किताबें पढ़ेंगे और जीवन के लिए यह दिशा-निर्देश तय करेंगे कि मन में नकारात्मक भावनाओं को आने नहीं देना है तो क्रोध, ईर्ष्या-द्वेष जैसी भावनाओं से काफी हद तक ऊपर उठ सकते हैं। अगर कोई क्रोध में आकर आपके साथ बुरा व्यवहार करता है तो उसकी प्रतिक्रिया में आपका नाराज होना उचित नहीं है। उस वक्त आप शांत रहें और तब आप उसे उसकी गलती का एहसास कराएं। कोई भी निर्णय लेते समय इंसान को अपनी

भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए क्योंकि भावावेश में आकर जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अकसर गलत साबित होता है।

भावनात्मक परिपक्वता

जब इंसान अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है तो वह स्वतः भावनात्मक परिपक्वता की ओर बढ़ने लगता है। जीवन में सफलता और सच्ची खुशी हासिल करने के लिए किसी भी व्यक्ति का भावनात्मक रूप से परिपक्व होना बहुत जरूरी है। कोई भी इंसान भावनात्मक रूप से कितना परिपक्व होगा, यह इस बात पर निर्भर है कि वह अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के प्रति कितना सचेत है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों में आठ सम्यक सूत्रों का उल्लेख मिलता है, जिनके माध्यम से जीवन के हर क्षेत्र में संतुलित आचरण अपनाने की शिक्षा दी गई है। गौतम बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से कहा था, तुम वीणा के तारों को इतना न कसो कि वे टूट जाएं और न ही इतना ढीला छोड़ो कि उनसे स्वर न निकले। कहने का अर्थ यह है कि भावनाओं की अभिव्यक्ति के मामले में हमेशा संतुलन होना चाहिए।

जानें किताब पढ़ने के फायदे...

पढ़ना एक ऐसी गतिविधि है जिसके कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। यदि आप नियमित रूप से नहीं पढ़ते हैं तो आपको रीडिंग को एक शौक के रूप में लेने पर विचार करना चाहिए। अक्सर लोगों के पढ़ने के पीछे के म्योजनों में कोई काम या शौक होता है। लेकिन वास्तव में पढ़ना एक ऐसी गतिविधि है जिसके कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। यदि आप नियमित रूप से नहीं पढ़ते हैं तो आपको रीडिंग को एक शौक के रूप में लेने पर विचार करना चाहिए। हर दिन एक किताब के कुछ पन्नों को पढ़ने के साथ धीरे-धीरे इसे शुरू करें या फिर समाचार देखने के बजाय अखबार पढ़ें। जल्द ही आपको अहसास होगा कि आप फिल्में देखने के बजाए किताबें पढ़ने की अच्छी आदत के मालिक हो चुके हैं।

तनाव कम होता है

किताब पढ़ना आपके तनाव को कम करता है, क्योंकि यह एक तरह की शांतिपूर्ण गतिविधि होती है। यह ऐसी गतिविधि नहीं है, जो आपके विचारों को उत्तेजित करे। हां, किताब पढ़ने के दौरान यह जरूर देखें कि आप किस तरह की किताब पढ़ रहे हैं। याद रहे कि अवसाद और तनावग्रस्त होने पर हमेशा दिमाग को शांत करने वाली या फिर मन को हल्का करने वाली किताब ही पढ़ें, आपको



अच्छा लगेगा।

अकेलापन दूर होता है

किताब पढ़ने का एक फायदा यह है कि ये आपका अकेलापन दूर करती है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, किताब आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। किताब तनाव से दूर ले जाती है और उन विचारों से दूर ले जाती है, जो आपको परेशान करते हैं।

फालतू बातों पर लगाम

किताब पढ़ने का एक फायदा यह है कि तनाव के दौरान तरह-तरह की फालतू बातें दिमाग में आती हैं। ऐसे

फंकी लुक और पार्टी वेयर ‘किमोनो’ है ट्रेंड में

फैशन जगत में भी लुक ईस्ट पॉलिसी पर फोकस किया जा रहा है। जापानी गुंडिया पर सजने वाली चीजें अब दुनिया के हर कोने के साथ-साथ भारत में भी खारी पसंद की जा रही हैं। ‘किमोनो’ भी इनमें से एक है। जो बहुत ही ट्रेंडी हैं। इस ढीले-ढाले परिधान को किसी भी ड्रेस के ऊपर पहना जा सकता है। इसे मॉडर्न आउटफिट कम टेंड्रिशनल कहा जा रहा है। बॉलीवुड हमेशा से ही ट्रेंड सेटर रहा है। दीपिका पादुकोण ने ‘किमोनो’ को भी काफी पापुलर बना दिया है। गल्सज अपने आप को डिफरेंट और अट्रैक्टिव दिखाने का प्रयास कर रही हैं, इसलिए यूनिक और स्टाइलिश ‘किमोनो’ टॉप्स में हैं। ये काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। अब गर्ल्स भी ‘किमोनो’ टॉप्स में नजर आ रही हैं जो की

उन्हें अट्रैक्टिव लुक दे रहा। ये लुक टीनेजर्स को बहुत लुभा रहा है। ‘किमोनो’ टॉप्स कलरफूल और सिम्पल लुक में भा रहे हैं। प्लेन और प्रिंटेड ‘किमोनो’ को जींस या पैटर्स के ऊपर पहन सकते हैं।

स्टाइलिश क्रेप व ‘किमोनो’ चलन में

कैजुअल लुक, फंकी लुक और पार्टी वेयर लुक के अलावा स्टाइलिश क्रेप और ‘किमोनो’ काफी चलन में हैं। नेट ‘किमोनो’ भी प्रचलित में हैं। मिनी स्कर्ट या शॉर्ट्स, फुल स्किनी ट्राउजर के साथ इसे कैरी कर सकते हैं और इसमें अटेंच बेल्ट से इसे कमर में टाइट कर सकते हैं। ये बैक साइड से पूरा कवर होता है और

समझें दूसरों की भावनाएं

भावनात्मक रूप से संतुलित होने के लिए खुद को समझने के साथ दूसरों की भावनाओं को भी समझने और उनके अनुरूप व्यवहार करने की कोशिश करनी चाहिए। इमोशनली इंटेलिजेंट लोगों का सामाजिक व्यवहार हमेशा संतुलित होता है। दूसरों के व्यक्तित्व की खूबियों-खामियों को पहचानने और उनके मन की बातों को पढ़ पाने का गुर जीवन के हर क्षेत्र में आपके काम आता है। चाहे वह आपका व्यक्तिगत जीवन हो या सार्वजनिक। अगर आप दूसरों को समझते हैं तो यह आपके लिए भी अच्छा होगा। दूसरों की भावनाओं को बारीकी से समझ पाना भावनात्मक विवेक का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

मुश्किल का हल



दफ्तर में जो व्यक्ति अपने साथियों के व्यक्तित्व को समझने में सफल होता है, अगर कभी उसके सामने कोई मुश्किल आती है तो वह आसानी से उसका हल ढूँढ लेता है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भी भावनात्मक रूप से संतुलित लोग अपने सभी संबंधों का निर्वाह अच्छी तरह कर पाते हैं। वे अपने जीवनसाथी, दोस्तों और रिश्तेदारों के व्यवहार को ध्यान से देखते हुए उनके व्यक्तित्व के सकारात्मक-नकारात्मक पक्षों को समझने की कोशिश करते हैं। लोगों के साथ उनका व्यवहार बेहद संयत होता है। उन्हें मालूम होता है कि अगर किसी से अपनी बात मनवानी भी है तो उसके सामने किस ढंग से पेश आना चाहिए। बच्चों की परवरिश के मामले में भावनात्मक संतुलन की भूमिका काफी अहम होती है।

व्यवहार कुशलता

समाज में लोगों के साथ व्यवहार के व्यवहार के आधार पर भी उसके भावनात्मक विवेक को आंका जाता है। भले ही किसी व्यक्ति से आपके वैचारिक मतभेद हों या किसी कारण से आप उसे नापसंद करते हों, लेकिन जब वह सामने मिले तो उसके साथ आपका व्यवहार हमेशा सहज और संतुलित होना चाहिए। जीवन के हर मोर्चे पर कामयाबी हासिल करने के लिए यह बहुत जरूरी है। अगर आप सचेत ढंग से इन सुझावों पर अमल करेंगे तो आपके लिए भावनात्मक संतुलन स्थापित करना आसान हो जाएगा।

संतुलन के कुछ सरल नियम

- इमोशन मैनेजमेंट डायरी**: अपने लिए एक इमोशन मैनेजमेंट डायरी बनाएं, रोजाना रात को सोने से पहले उसमें दर्ज करें कि पूरे दिन में आपने कितनी बार और किन स्थितियों में नकारात्मक व्यवहार किया, ताकि अगली बार वैसी स्थिति में आप अपने व्यवहार में सुधार ला सकें।
- यह आदत डालें**: समस्याओं से दुखी होने के बजाय उन्हें हल करने की आदत डालें।घर और बाहर दोनों जगहों पर लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने और बिगड़े हुए संबंध को सुधारने की कोशिश करें। अपनी भावनाओं की अभिव्यवित पर नियंत्रण रखें और सहनशक्ति को मजबूत बनाएं।
- भावुक क्षणों में फैसला न लें**: भावुक क्षणों में कोई भी निर्णय न लें क्योंकि इसमें अकसर गलतियां हो जाती हैं। ऐसे लोगों के पूरे स्ती बदवाएं, जिनसे बातें करके आपको खुशी मिलती है। अच्छे सामाजिक संबंध भावनात्मक संतुलन बनाने में मददगार होते हैं।
- असफलताएं हैं जीवन का हिस्सा**: करियर के क्षेत्र में मिलने वाली छोटी-छोटी असफलताओं को पहले से ही अपने जीवन का जरूरी हिस्सा मानकर चलें। अपनी नाकामी से निराश होने के बजाय यह संकल्प लें कि दोबारा आपके साथ ऐसा नहीं होगा। अगर आप छात्र हैं या करियर बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं तो अपनी क्षमताओं का सही मूल्यांकन करना सीखें।
- अपनी क्षमताओं को जानें**: अपनी क्षमता के अनुरूप ही परिणाम की आशा रखें। अति महत्वाकांक्षा और उसके पूर्ण न होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति भावनात्मक रूप से असंतुलित हो जाता है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अपने प्रोफेशन के संबंध में निरंतर नई जानकारीयां हासिल करें और काम की नई तकनीकें सीखते रहें। इससे आप स्वयं को हमेशा युवा और ऊर्जावान महसूस करेंगे।
- अपने ऊपर ध्यान दें**: अगर ऐसा लगता है कि वाकई आपका भावनात्मक संतुलन बिगड़ रहा है तो अपने ऊपर पूरा ध्यान दें। पर्याप्त नींद लें, योगाभ्यास और ध्यान करें।परिवार के साथ पूरा समय बिताएं। छुट्टियों में कहीं घूमने जाएं। हमेशा अच्छा सोचें। इससे जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे।

सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचने लगते हैं, पर किताब पढ़ने के दौरान आपके सामने कई सारी ऐसी बातें होती हैं, जो आप पर केन्द्रित नहीं होती हैं। ऐसे में एक तरह से आपकी अन्य बातों को सोचने की क्षमता का विकास ही होता है।

मस्तिष्क का व्यायाम

पढ़ना एक प्रकार बेहतर तरीके से मस्तिष्क को उद्दीप्त करना करता है, जोकि टीवी देखने या रेंडियो सुनने से कभी नहीं हो सकता। फिर भले ही आप कोई नया थियर पढ़ रहे हों या फिर अपने डीवीडी प्लेयर का अनुदेश मैनुअल, पढ़ने से आपका मस्तिष्क संलग्न रहता है और उसकी एक्ससाइज होती है।

याददाश्त बढ़ती है

जो लोगो पढ़ाई करते रहते हैं उनकी याददाश्त तेज होती है। टीवी देखने और कंप्यूटर पर काम करने की तुलना में पढ़ाई करने वालों का दिमाग अधिक तेज होता है। इसके अलावा पढ़ने की आदत व्यक्ति के सोचने और समझने की क्षमता को भी बढ़ाती है।

दिमाग जवां रहता है

पढ़ने की आदत से इंसान का दिमाग हमेशा जवां रहता है। एक शोध के अनुसार, वे लोग जो रचनात्मक कामों जैसे पढ़ाई आदि में अधिक समय बिताते हैं, उनका दिमाग ऐसा न करने वाले लोगों की तुलना में 32 प्रतिशत तक अधिक युवा बना रहता है।

अल्जाइमर से बचाव

अल्जाइमर उम्रदराज लोगों में होने वाला एक मानसिक रोग है, जिसके कारण व्यक्ति की याददाश्त कमजोर हो जाती है। जो दिमागी गतिविधियों जैसे, पढ़ाई, चेस खेलना, पजल हल करना आदि में व्यस्त रहते हैं।

सामने से हाफ ओपन होता है ताकि अंदर जो जीन्स और स्कर्ट पहना है वो नजर आ सके। ये गर्ल्स को स्टाइलिश लुक दे। जापानी ‘किमोनो’ का डिजाइनर आउटफिट्स काफी लड़कियों को लुभा रहा है जो स्लीवलेस कुर्ती और टी सर्ट के साथ कैरी किया जा रहा है।

फॉलो कर रही हैं

इस सीजन में सबसे ज्यादा चलन में है तो वो है ‘किमोनो’ । गर्ल्स ये ट्रेंड फॉलो कर रही हैं। यही नहीं इसमें भी नए-नए इन्वोवेशन देखने को मिल रहे हैं।

इसे जींस के साथ कैरी किया जा सकता है तो वहीं प्लाजो के साथ भी इसे पहना जा सकता है। कैजुअल लुक, फंकी लुक और पार्टी वेयर लुक के लिए भी इसे ट्राय कर सकते हैं। ये नया ट्रेंड है और कूल भी है।

जंतर-मंतर का सीजन-2 आने वाला है: अभिजीत दीपके
नई दिल्ली। काँकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने जंतर-मंतर के सीजन-2 को लेकर बड़ा एलान किया है। उन्होंने लोगों को बताया है कि जंतर-मंतर का सीजन-2 जल्दी ही आएगा। अभिजीत दीपके ने कहा, बहुत से लोग इस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि जंतर-मंतर का सीजन 2 कब शुरू होगा। मैं उन्हें बताया चाहता हूँ कि जंतर-मंतर का सीजन 2 बहुत जल्द शुरू होने वाला है। काँकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि वे लोग उन्हें वॉलंटियर्स मीट के लिए हॉल नहीं मिलाने दे रहे। दीपके ने आज बुधवार को कहा कि आज दिल्ली में हमारी वॉलंटियर्स मीट होनी थी, दूर-दूर से हमारी पार्टी से जुड़े लोग आए थे, लेकिन हमारी मीटिंग नहीं होने दी जा रही। अभिजीत दीपके ने कहा, %आज दिल्ली में हमारे वॉलंटियर्स की मीटिंग होनी थी। हम हॉल ढूँढ रहे थे, लेकिन कोई भी हमें हॉल किराए पर देने को तैयार नहीं था। हर कोई यही कह रहा था कि ऊपर से दबाव है।

आईपीएल स्टार अभिषेक पोरेल गिरफ्तार
कोलकाता। दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं. भारतीय क्रिकेट को मंगलवार सुबह हुगली में पुलिस ने हिरासत में लिया और कई घंटे की पूछताछ के बाद दोपहर में औपचारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया. यह कार्रवाई शादी का झंसा देकर यौन संबंध बनाने के आरोप से जुड़े मामले में हुई है.गिरफ्तारी के बाद अभिषेक पोरेल का मेडिकल परीक्षण कराया गया. इसके बाद उन्हें चुंचुड़ा कोर्ट में पेश किया गया. मामले में मंगलवार को ही अग्रिम जमानत पर सुनवाई भी तय थी. इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने पुलिस को अभिषेक पोरेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था. हुगली जिला अदालत ने अभिषेक पोरेल को तीन दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है. यह मामला हुगली के मोगरा थाने में एक मेडिकल छात्र की शिकायत के बाद सामने आया. महिला ने आरोप लगाया कि अभिषेक पोरेल ने शादी का वादा करके उसके साथ यौन संबंध बनाए. शिकायत में यह भी दावा किया गया है।

यूएस में अडानी के खिलाफ आपराधिक केस खारिज
नई दिल्ली। उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में चल रहा आपराधिक मामला सोमवार को खारिज कर दिया गया. अमेरिकी जज निकोलस गरीफिस ने अडानी पर लगे आरोपों को हटाने की मंजूरी दी, लेकिन साथ ही अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के मामले वापस लेने के तरीके पर गंभीर सवाल भी उठाए. जज ने कहा कि केस खत्म करने की प्रक्रिया में जो गड़बड़ियां सामने आई हैं, वे चिंता बढ़ाने वाली हैं.यह फैसला उस सुनवाई के बाद आया, जिसमें जज गरीफिस ने खुद जस्टिस डिपार्टमेंट से मामला वापस लेने की वजह पूछी थी. अदालत ने यह भी जांचा कि क्या नवंबर 2024 में अमेरिका में 10 अरब डॉलर के निवेश के गौतम अडानी के वादे का केस खत्म करने के फैसले से कोई संबंध था. बाद में जज ने कहा कि उन्हें संतोष है कि वह निवेश प्रस्ताव मामले को खारिज करने के फैसले का आधार नहीं था. इस फैसले के बाद गौतम अडानी की प्रतिक्रिया भी सामने आई।

ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार को बेल से इनकार
नई दिल्ली। ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार को छत्रसाल स्टेडियम में पूर्व जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने सुशील कुमार को नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी. जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार ने 6 अगस्त को यह फैसला सुनाया.कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए अपराध की गंभीरता के साथ-साथ गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका को भी अहम आधार माना. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कथित हमला पहले से तय और बेहद गंभीर था, जिसके चलते सागर धनखड़ की मौत हुई. मामले में हथियार की बरामदगी, वीडियो सबूत और बड़ी मात्रा में अन्य सामग्री भी मौजूद है, जिसकी ट्रायल के दौरान जांच होनी बाकी है.दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि सामान्य तौर पर जमानत नियम और जेल अपवाद है, लेकिन मौजूदा मामले की परिस्थितियां अलग हैं. अदालत ने कथित वारदात को पूर्व नियोजित और वीभत्स हमला बताया, जिसके परिणामस्वरूप सागर धनखड़ की मौत हुई।

फ्लाइट हादसे पर एयर इंडिया के सीईओ को समन
नईदिल्ली। एयर इंडिया के आउटगोइंग सीईओ कैपबेल विल्सन को मंगलवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुख्यालय में बैठक के लिए बुलाया गया था. एयर इंडिया की फ्लाइटAI2379 में हुई घटना के कुछ दिनों बाद सरकार ने एयरलाइन से जुड़े सुरक्षा और संचालन संबंधी मुद्दों की समीक्षा के लिए यह बैठक बुलाई थी. बैठक में नागरिक उड्डयन सचिव, एयरकापट एक्स्रीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी बैठक में शामिल हुए. बैठक अब खत्म हो चुकी है.सूत्रों के मुताबिक, बैठक में एयर इंडिया से जुड़े बड़े मुद्दों के साथ 4 अगस्त को हुई फुकेट-दिल्ली उड़ान की घटना पर भी चर्चा हुई, जिसमें 17 यात्री और कर्ू सदस्य वायल हुए थे. सूत्रों के अनुसार, कैपबेल विल्सन से AI2379 घटना को लेकर सवाल किए गए.दरअसल, 4 अप्राप्त को फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइटU AI2379, जो एयरबस 320 थी।

प्रधानमंत्री का देश के जेन-जी को नया संदेश

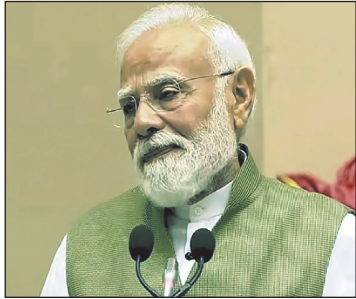
देश का भविष्य ही नहीं, वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति हैं युवा : मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बुधवार को सुभाषित शेयर किया है। पीएम मोदी ने अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भारतीय के युवाओं को देश की सबसे बड़ी शक्ति भी बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं के प्रयासों की सराहना करते हुए %एक्स% पोस्ट पर लिखा, %हमारे युवा साथी देश का भविष्य ही नहीं, वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति भी हैं। उन्होंने अपनी संवेदनशीलता, सेवाभाव और सामर्थ्य से दुनियाभर में अलग पहचान बनाई है।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने संस्कृत का श्लोक भी एक्स पर पोस्ट किया, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम्। प्रसादयति यो लोकं तं लोकोऽनुप्रसीदति॥ इस श्लोक का हिंदी अर्थ है- जो व्यक्ति अपनी दृष्टि, विचारों, वाणी और कर्मों के माध्यम से लोगों का हृदय जीत लेता है, वह ही उनके विश्वास, सम्मान और सद्भाव का पात्र बनता है।

जेन-जी को इन्फ्लुएंसर्स से वचन की दी सलाह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत की जेन-ज़ी पीढ़ी के लिए एक संदेश है: रील्स, इन्फ्लुएंसर्स और तुरंत संतुष्टि पाने की चाहत वाले इस दौर में शॉर्टकट से सावधान रहें। रेलवे स्टेशनों से दी जाने वाली एक जानी-पहचानी चेतावनी का जिक्र करते हुए, पीएम मोदी ने युवाओं से लंबा और ज्यादा सार्थक रास्ता चुनने का आग्रह किया। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे कुछ लोग फुटब्रिज का इस्तेमाल



करने के बजाय रेलवे ट्रेक पार करते हैं, क्योंकि उन्हें यह रास्ता ज्यादा जल्दी वाला लगता है। उन्होंने कहा कि ऐसी क्रॉसिंग पर लिखी चेतावनी एक बड़ी सीख देती है। उन्होंने कहा शॉर्टकट आपकी जिंदगी छोटी कर सकता है। साथ ही, उन्होंने युवाओं को उन इन्फ्लुएंसर्स से सावधान रहने की सलाह दी जो अक्सर उन्हें अलग-अलग दिशाओं में ले जाते हैं। दक्षिण-एशियाईऔर प्रवासी

प्रधानमंत्री ने बुधवार को दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ़, माय स्ट्रगल्स के लॉन्च के मौके पर ये बातें कहीं। युवाओं से उनकी यह अपील ऐसे समय में आई है जब उस पीढ़ी से जुड़ने की कोशिश की जा रही है जो हर समय ऑनलाइन रहती है। पीएम मोदी ने कहा अगर आप आगे बढ़ने का कोई रास्ता खोजना चाहते हैं, तो मैं युवाओं से कहूंगा: आप जिसे भी अपना आदर्श मानते हैं, उनकी आत्मकथा जरूर पढ़ें।

पिछले महीने काँकरोच जनता पार्टी नाम के व्यंग्यात्मक प्लेटफॉर्म के नेतृत्व में हुए छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के बाद,

प्रधानमंत्री का जेन-जी तक पहुंचने का यह एक और प्रयास है। उनकी सोशल मीडिया रणनीति में युवा यूजर्स के बीच लोकप्रिय भाषा और फॉर्मेट का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ा है। पीएम मोदी ने अब ज्यादा सेल्फी-स्टाइल वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने दर्शकों का अनौपचारिक अंदोज में हाय, दोस्तों! कहकर स्वागत किया है, मेरे परिवार में पहला जैसे वायरल पुरेज़ का इस्तेमाल किया है और सोशल मीडिया पर पारंपरिक भारतीय कपड़ों को दिखाने के लिए GRVVM (मेरे साथ साथ हो) फॉर्मेट को अपनाया है। यह बदलाव नीट-यूजी पेपर लोक को लेकर छात्रों और नौकरी चाहने वालों के देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बाद आया। ये प्रदर्शन सरकार के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बन गए और आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा।

बीजेपी और उसके मूल संगठन, आरएसएस ने भी उसाओं तक अपनी पहुँच बढ़ाने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। मंत्री और सरकारी विभाग तेज़ी से शॉर्ट-फॉर्म वीडियो का इस्तेमाल करने लगे हैं। असल में, विदेश मंत्रालय ने पिछले हफ्ते ही स्नैपचैट पर अपनी शुरुआत की है।

विरोध-प्रदर्शनों के बाद हुई कैबिनेट की बैठक में, पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा कि वे युवाओं के बीच लोकप्रिय प्लैटफॉर्म पर ज्यादा सक्रिय हों और यह पक्का करें कि उनके वीडियो बहुत ज्यादा पॉलिश किए हुए न लगे, बल्कि लोगों को अपने जैसे और जुड़े हुए लगे।

सेंसेक्स 187 अंक लुढ़का निफ्टी 24450 के नीचे बंद

नईदिल्ली। घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार को (12 अगस्त) कमजोरी दर्ज की गई। बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के इस्तीफे से टाटा ग्रुप स्टॉक्स फोकस में रहे। इसके अलावा गोदेरज ग्रुप स्टॉक्स समेत नतीजों वाले शेयरों में हलचल देखने को मिली। हालाँकि, क्लोसिंग से पहले आई खरीदारी से बाजार में अच्छी रिकवरी देखने को मिली। एनएसई का निफ्टी क्रीब 35 अंक फिसलकर 24435 पर बंद हुआ, जोकि कारोबारी सेशन में 24265 तक फिसल गया था। बीएसई का सेंसेक्स भी क्रीब 187 अंकों की गिरावट के साथ 77966 पर बंद हुआ, जोकि 78,263 पर खुला था। बाजार की कमजोरी में टाटा ग्रुप के शेयर फोकस में रहे। चंद्रशेखरन के इस्तीफे के बाद टीसीएस इंट्राडे में 5 फीसदी से ज्यादा फिसला, जोकि 3.9 फीसदी गिरकर बंद हुआ।

हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल हुआ महंगा

शिमला। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का विधवा और अनाथ सेस लगाने के बाद ईंधन की कीमतें बढ़ गई हैं। इसी तरह, हाई-स्पीड डीजल पर भी 60 पैसे प्रति लीटर का अतिरिक्त सेस लगाया गया है। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, यह सेस हिमाचल प्रदेश वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2005 की धारा 6-ए के तहत लगाया जाएगा। सेस लगने के बाद, राजधानी शिमला में पेट्रोल की कीमत 102.45 रुपये से बढ़कर 103.05 रुपये प्रति लीटर हो गई है। धर्मशाला में पेट्रोल की कीमतों में 71 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल की कीमतों में 69 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। यह फ्यूल सेस, हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा इस साल के बजट सत्र में पारित हुआ था।

भारत की विनिर्माण रणनीति में बड़ी खामी, औद्योगिक आधार मजबूत करना बहुत जरूरी

अजय श्रीवास्तव

भारत की औद्योगिक रणनीति में एक गंभीर खामी है। नीति निर्माताओं ने सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, ड्रोन, रोबोटिक्स और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) में संसाधनों का भरपूर निवेश किया है, लेकिन उन्होंने उन हजारों औद्योगिक उत्पादों की अनदेखी की है जिन पर हर सफल विनिर्माण अर्थव्यवस्था टिकी होती है। इनमें मशीन टूल्स, बियरिंग, पंप, वाल्व, इलेक्ट्रिक मोटर्स, कंप्रेसर, गियर, फास्टरर्स, औद्योगिक रसायन, ट्रांसफॉर्मर, केबल और हजारों अन्य इंजीनियरिंग उत्पाद शामिल हैं। ये उन्नत विनिर्माण की नींव हैं।

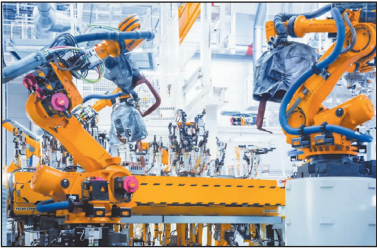
भारत को अत्याधुनिक तकनीकों में निवेश जारी रखना चाहिए, लेकिन जब तक वह इन औद्योगिक बुनियादी उत्पादों में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी नहीं बन जाता, तब तक वह एक वास्तविक विनिर्माण शक्ति बनने

के बजाय एक असेंबली अर्थव्यवस्था ही बना रहेगा।

विनिर्माण को तीन-स्तरों के पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। सबसे निचले स्तर पर इस्पात, एल्युमीनियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स जैसे औद्योगिक कच्चे माल हैं। सबसे ऊपरी स्तर पर सेमीकंडक्टर, एआई, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, एरोस्पेस और रोबोटिक्स जैसे उभरते उद्योग हैं। इन दोनों के बीच सबसे बड़ा स्तर है-औद्योगिक आधारभूत उत्पाद जो कच्चे माल को तैयार माल से जोड़ते हैं।

ग्राहक तक पहुंचने से पहले प्रत्येक इलेक्ट्रिक वाहन को मोटर, बियरिंग, गियर, फास्टर, वायरिंग, मोल्ड, डाई और मशीन टूल की आवश्यकता होती है। इस मध्यवर्ती स्तर को अनदेखा करने पर, संपूर्ण विनिर्माण प्रणाली आयात पर निर्भर हो जाती है।

पिछले दो दशकों में, भारत की



औद्योगिक नीति का अधिकांश ध्यान उभरते उद्योगों पर केंद्रित रहा है। मेक इन इंडिया, उत्पादन-लिंकड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, एफएमई यानी फेम, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं ड्रोन कार्यक्रमों जैसी पहलों के माध्यम से सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अरबों डॉलर का निवेश किया गया है।

इस रणनीति से लाभ हुआ है।

सरकार ने ओला इलेक्ट्रिक के लिए समयसीमा में किया बदलाव

नई दिल्ली। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड ने बुधवार को कहा कि भारी उद्योग मंत्रालय ने उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी ओला सेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (ओसीटी) के लिए उन्नत रसायन सेल (एसीसी) उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत संशोधित समयसीमा को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने बयान में कहा कि एमएचआई का यह संशोधन महज समयसीमा बढ़ाने तक सीमित नहीं है। मंजूरी से ओला इलेक्ट्रिक को उसके 20 गीगावाट आवेदन के लिए 2031 तक पूरे पांच साल की पीएलआई अवधि मिलेगी और कुल 7,240 करोड़ रुपये तक के पीएलआई प्रोत्साहन मिल सकेगा। इसमें कहा गया कि प्रोत्साहन राशि का भुगतान अगली तिमाही से शुरू होगा और यह तिमाही आधार पर किया जाएगा। इससे कंपनी के सेल कारोबार के विस्तार के साथ नियमित प्रोत्साहन आय का प्रवाह बनेगा।

वस्तु निर्यात 131 अरब डॉलर के पार पहुंचने की संभावना

नई दिल्ली। भारत के निर्यात-आयात बैंक (एफिजम बैंक) ने अनुमान लगाया है कि देश का कुल वस्तु निर्यात चालू वित्त वर्ष 2026–27 की दूसरी तिमाही में 131 अरब डॉलर के पार पहुंच जायेगा। एफिजम के अनुसार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि दूसरी तिमाही में वस्तु निर्यात 17.6 प्रतिशत बढ़कर 131.2 अरब डॉलर रहने की संभावना है। इस अवधि में गैर-तेल निर्यात में 20.3 प्रतिशत और गैर-तेल तथा गैर-रब एवं आभूषण निर्यात में 20.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। गैर-तेल निर्यात 113.8 प्रतिशत और गैर-तेल तथा गैर-रब एवं आभूषण निर्यात 105.8 अरब डॉलर रहने की संभावना जताई गई है। कुल वस्तु निर्यात की वृद्धि का अनुमान एफिजम बैंक द्वारा प्रत्येक तिमाही में जारी किया जाता है।

शुरुआत करके विश्व का कारखाना नहीं बना। उसने पहले हजारों औद्योगिक आधारभूत उत्पादों में महारत हासिल की, जिससे आपूर्तिकर्ताओं, उपकरण कंपनियों, घटक निर्माताओं और इंजीनियरिंग फर्मों का सघन नेटवर्क स्थापित हुआ। एक बार यह आधार तैयार हो जाने के बाद, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, बैटरी और नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग तेजी से विकसित हुए। भारत लगभग इसके विपरीत प्रयास कर रहा है।

1980 के दशक के उत्तरार्ध में भारत और चीन ने लगभग समान विनिर्माण स्तरों से शुरुआत की थी, लेकिन 1990 के दशक के बाद उनके रास्ते अलग हो गए। चीन ने अपने विनिर्माण तंत्र को लगातार मजबूत किया, जबकि भारत की औद्योगिक रीढ़ कमजोर हो गई। कुछ नीतिगत फैसलों ने इस परिणाम में योगदान दिया।

अवसरों का महाकुंभ

रोजगार, कौशल और स्वरोजगार से सशक्त होता युवा छत्तीसगढ़

रोजगार मेलों से लाखों अवसर, कौशल विकास से आत्मनिर्भरता और निवेश से खुल रहे रोजगार के नए द्वार

छत्तीसगढ़ का युवा अब नौकरी खोजने वाला नहीं, रोजगार सृजित करने वाला बन रहा है

“छत्तीसगढ़ का युवा हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हमारा लक्ष्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि ऐसा वातावरण तैयार करना है जहां हर युवा अपनी प्रतिभा, कौशल और नवाचार के बल पर आत्मनिर्भर बन सके। रोजगार मेले, कौशल विकास, आधुनिक शिक्षा, स्टार्टअप प्रोत्साहन और औद्योगिक निवेश के माध्यम से हम अवसरों का ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं, जहां युवा नौकरी खोजने के बजाय रोजगार सृजन का नेतृत्व करें। विकसित छत्तीसगढ़ का सपना युवा शक्ति की ऊर्जा और सामर्थ्य से ही साकार होगा।

-विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ आज युवाओं के लिए अवसरों की नई धरती बनकर उभर रहा है। रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता और निवेश को केंद्र में रखकर तैयार की गई नीतियों ने राज्य में विकास की ऐसी मजबूत नींव रखी है, जहां युवा केवल नौकरी पाने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि स्वयं रोजगार सृजित करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है।

रोजगार मेलों से लेकर ई-रोजगार पोर्टल, मॉडल करियर सेंटर, आधुनिक आईटीआई, लाइवलीहुड कॉलेज, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, स्टार्टअप प्रोत्साहन और नई औद्योगिक नीति तक, सरकार की बहुआयामी पहलें युवाओं को कौशल, अवसर और आत्मविश्वास प्रदान कर रही हैं। यही कारण है कि वर्ष 2026 में छत्तीसगढ़ रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है।

रोजगार महाकुंभ: युवाओं और उद्योगों के बीच मजबूत सेतु

- राजधानी रायपुर सहित विभिन्न संभागों में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेलों में हजारों युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार।
- तकनीकी व गैर-तकनीकी दोनों श्रेणियों में बड़ी संख्या में रिक्त पदों पर भर्ती।
- उद्योगों और कंपनियों को एक मंच पर लाकर पारदर्शी और तेज चयन प्रक्रिया।
- बस्तर और सरगुजा अंचल के युवाओं के लिए विशेष साक्षात्कार सत्र का आयोजन।



ई-रोजगार पोर्टल: घर बैठे नौकरी तक पहुंच

- पंजीयन, नवीनीकरण और रोजगार जानकारी पूरी तरह ऑनलाइन।
- आधार आधारित प्रमाणीकरण, ऑनलाइन प्रमाणपत्र और एसएमएस अलर्ट की सुविधा।
- रिक्त पदों, रोजगार मेलों और करियर संबंधी जानकारी सीधे मोबाइल तक।

मॉडल करियर सेंटर: करियर मार्गदर्शन का नया अध्याय

- राज्य के विभिन्न जिलों में मॉडल करियर सेंटर स्थापित।
- करियर काउंसलिंग, प्लेसमेंट सहायता, प्रतियोगी परीक्षा मार्गदर्शन और रोजगार सूचना उपलब्ध।
- राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS) से एकीकृत होकर देशभर के अवसरों तक पहुंच।

पारदर्शी भर्ती व्यवस्था से लौटा युवाओं का विश्वास

- प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित।
- रिक्त पदों पर नियमित भर्ती, युवाओं के भरोसे को मिली नई मजबूती।
- सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में समान रूप से रोजगार के अवसरों का विस्तार।

कौशल विकास: रोजगार की मजबूत नींव

- मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण।
- 2.7 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया।
- 356 प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाएं और 207 रोजगारपरक कोर्स संचालित।
- इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, मैकेनिक, मशीन ऑपरेटर, आईटी तकनीशियन जैसे ट्रेडों में व्यापक प्रशिक्षण।

आधुनिक ITI और लाइवलीहुड कॉलेज बदल रहे तस्वीर

- प्रदेश के 145 शासकीय ITI का आधुनिकीकरण और नए भवनों का निर्माण।
- नवा रायपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित।
- जगरगुंडा, ओरछा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में नए ITI स्थापित।
- पीएम सेतु योजना के तहत क्लस्टरों में ITI उन्नयन।



कौशल आधारित प्रशिक्षण युवाओं को रोजगार के लिए बना रहा है तैयार

उत्कृष्टता केंद्र: डिग्री से आगे, ग्लोबल करियर की तैयारी

- प्रमुख महाविद्यालयों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, डिजिटल लर्निंग सेंटर, रिसर्च एवं इनोवेशन लैब।
- AI, डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण।
- स्टार्टअप इनक्यूबेशन और करियर गाइडेंस की विशेष सुविधाएं।

आंकड़ों में उपलब्धियां

5 लाख +	2.7 लाख +	356	207	145
युवाओं को प्रशिक्षण	युवाओं को रोजगार	प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाएं	रोजगारपरक कोर्स	ITI का आधुनिकीकरण

स्टार्टअप संस्कृति: युवा बन रहे जॉब क्रिएटर

- स्टार्टअप प्रोत्साहन नियमों के तहत आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन।
- ई-हब, इनक्यूबेशन सेंटर और नवाचार प्लेटफॉर्म से सहयोग।
- हजारों स्टार्टअप विकसित कर युवाओं को उद्यमी बनाया जा रहा है।



उद्योग, निवेश और रोजगार का नया समीकरण

- नई औद्योगिक नीति 2024-30 में रोजगार सृजन को केंद्र में रखा गया।
- लाखों करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव, 1.5 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार की संभावना।
- 1000+ रोजगार देने वाले उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन।

सेमीकंडक्टर, AI और ग्रीन इंडस्ट्री से खुलेंगे नए अवसर

- सेमीकंडक्टर निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, AI, सौर ऊर्जा, टेक्सटाइल, बायो-एथेनॉल में नए निवेश।
- नवा रायपुर को IT हब के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- उच्च गुणवत्ता वाले तकनीकी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

पर्यटन, कृषि और स्थानीय संसाधनों से बढ़ रहा स्वरोजगार

- बस्तर और सरगुजा में होम स्टे, एग्रो प्रोसेसिंग, वन उत्पाद आधारित उद्यमों को बढ़ावा।
- चित्रकोट, सिरपुर जैसे पर्यटन स्थलों के विकास से स्वरोजगार के अवसर।
- हजारों युवाओं और महिलाओं के लिए आय का नया स्रोत।

छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्ती का नया युग, बना कर्मचारी चयन मंडल

- 30 अप्रैल 2026 को छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (CSSB) की स्थापना कर राज्य में नई भर्ती व्यवस्था लागू की गई।
- तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर सीधी भर्ती अब इसी मंडल के माध्यम से होगी।
- समान योग्यता वाले पदों के लिए एकल संयुक्त परीक्षा आयोजित होगी, जिससे अलग-अलग परीक्षाओं की आवश्यकता नहीं रहेगी।
- भर्ती प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा।
- नई व्यवस्था से युवाओं का समय और धन बचेगा तथा राज्य के अधिकांश विभागों की भर्तियां एक ही मंच से संचालित होंगी।

रोजगार का विस्तार • कौशल का विकास • उद्यमिता को प्रोत्साहन • निवेश से समृद्धि • आत्मनिर्भर युवा, समृद्ध छत्तीसगढ़